▸▸वर्ष : 34 ▸▸अंक : 362 ▸▸मुंबई, बुधवार, 11 मार्च 2026 ▸▸RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸मूल्य : 3 रुपए ▸▸epaper.dobajedopahar.com ▸▸संपादक : अरुण लाल ▸▸संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD
दो बजे दोपहर
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

सरकारी एक्शन

महंगाई और ईंधन पर कड़ी नज़र

मध्य पूर्व में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम उठाया है। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो, उसका खामियाजा भारत के आम नागरिक को नहीं भुगतना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को 'साइलो' (अकेले-अकेले काम करने) के बजाय मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उनका मानना है कि जब अंतरराष्ट्रीय संकट बड़ा हो, तो वित्त, विदेश, पेट्रोलियम और वाणिज्य मंत्रालयों के बीच तालमेल ही देश को सुरक्षित रख सकता है।

कच्चे तेल और गैस के लिए प्लान-बी

भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कच्चे तेल और गैस की आयात रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब भारत केवल कुछ ही देशों या रास्तों पर निर्भर नहीं है। सरकार ने वैकल्पिक समुद्री रास्तों का उपयोग शुरू कर दिया है, ताकि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के कारण सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए।

राहत

केंद्र के निर्देश के बाद रिफाइनरियों ने बढ़ाया एलपीजी उत्पादन

घरेलू उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत की तेल रिफाइनरियों ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उत्पादन करीब 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

देश में एलपीजी संकट

डीबीडी संवाददाता । नई दिल्ली/मुंबई

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच पूरी दुनिया में गैस की सप्लाई टाइट हो गई है। भारत की सबसे ज्यादा गैस कतर से आती है लेकिन खाड़ी के इस देश ने सप्लाई बंद कर दी है। इससे देश में गैस का संकट खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक वस्तु कानून लागू कर दिया है। सरकार ने साथ ही रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी का अधिकतम उत्पादन करने को कहा है।

▸▸दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों के होटल और रेस्टोरेंट्स पर बंद होने का खतरा

▸▸सरकार ने गैस आवंटन में बदलाव किया, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी को मिलेगी प्राथमिकता

मुंबई के 20% होटलों पर लगा ताला

मुंबई में गैस की सप्लाई कम होने की वजह से कई होटल मुश्किल में आ गए हैं। होटल संगठन आहार के मुताबिक, गैस की कमी के चलते मुंबई के करीब 20% होटल फिलहाल बंद हो चुके हैं। संगठन ने कहा कि अगर गैस की सप्लाई जल्दी ठीक नहीं हुई तो अगले दो दिनों में करीब 50 परसेंट होटल को बंद करने की नौबत आ सकती है। अभी तक होटल बंद करने का कोई सामूहिक फैसला नहीं लिया गया है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) के उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने कहा कि पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं।

सरकार ने गैस आवंटन में किया बदलाव

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन में बदलाव किया है। इसके तहत एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) को अन्य सभी क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण भारत की एक-तिहाई गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलने वाली गैस प्रमुख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। भारत अपनी 19.1 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन गैस खपत का लगभग आधा हिस्सा आयात के जरिये पूरा करता है। होर्मुज से टैंकर की आवाजाही रुकने के कारण पश्चिम एशिया से आने वाली करीब छह करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन की गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है।

महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा एलपीजी संकट और युद्ध का असर

महाराष्ट्र बजट सत्र के दौरान शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस वैश्विक अस्थिरता को रोकने के लिए कोई कूटनीतिक पहल की जा रही है, ताकि आम जनता और व्यापार पर इसका बोझ न पड़े।

सरकार का आश्वासन: घरेलू आपूर्ति रहेगी बरकरार

विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता घरेलू गैस (Domestic Gas) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने जिला कलेक्टरों को जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि, सरकार ने संकेत दिए कि संकट की स्थिति में कमर्शियल गैस की आपूर्ति कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसे लंबा नहीं खींचने दिया जाएगा।

होटल उद्योग पर संकट और सरकारी निगरानी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि होटल मालिकों ने कमर्शियल गैस की कमी को लेकर चिंता जताई है और आपूर्ति में 25% कटौती का सुझाव दिया है। इस विषय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा की गई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और गैस स्टॉक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था और होटल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर न्यूनतम असर पड़े।

सोशल मीडिया पर बदनाम करना पड़ेगा महंगा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में सोशल मीडिया के जरिए किसी की छवि खराब करने और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने 'एक्शन मोड' में आने का फैसला किया है। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस डिजिटल खतरे से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। यह समिति इस बात का गहराई से अध्ययन करेगी कि सोशल मीडिया पर लोग कैसे दूसरों की बदनामी करते हैं और फर्जी जानकारी फैलाते हैं। समिति मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगी और सरकार को सुझाव देगी कि इन मामलों में और अधिक प्रभावी और सख्त कार्रवाई कैसे की जा सकती है।

▸▸डीजीपी की अध्यक्षता में बनेगी विशेष समिति

▸▸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान

'अभिव्यक्ति की आजादी' और 'दुरुपयोग' के बीच संतुलन

सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म करना नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग को रोकना है। विधानसभा में विधायकों ने चिंता जताई कि बिना सबूत के किसी के खिलाफ अभियान चलाना एक फैशन बन गया है। यह समिति एक ऐसा नियम बनाएगी जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग जिम्मेदारी से व्यवहार करें और किसी की निजी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुँचे।

नई तकनीक से 'स्मार्ट' होती ठगी

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने सदन को बताया कि अब अपराधी एडिट किए गए वीडियो, फर्जी अकाउंट और डिजिटल ठगी के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इन 'हाई-टेक' अपराधियों को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र की साइबर सेल को भी आधुनिक तकनीक और हथियारों (सॉफ्टवेयर) से अपडेट किया जा रहा है।

जागरूकता के लिए 'स्पेशल मोबाइल ऐप'

केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए सरकार ने एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। इस ऐप के जरिए हर महीने राज्य के करोड़ों नागरिकों को सुरक्षा संदेश भेजे जाएंगे। इसका मकसद लोगों को यह सिखाना है कि वे ऑनलाइन ठगी, फर्जी खबरों और किसी भी तरह की डिजिटल बदनामी से खुद को कैसे सुरक्षित रखें।

180 दिनों की मैटरनिटी लीव मंजूर

▸▸बिना मेडिकल सर्टिफिकेट 1 साल की अतिरिक्त छुट्टी का भी प्रावधान

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने विधानसभा में घोषणा की कि अब राज्य की महिला कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार की तर्ज पर 180 दिनों (6 महीने) की सवैतनिक छुट्टी मिलेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अब उन्हें प्रसूति के दौरान 6 महीने की पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर 180 दिनों के बाद भी बच्चे की देखभाल के लिए समय चाहिए, तो महिला कर्मचारी बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के 1 साल तक का 'अर्ध-वेतन अवकाश' ले सकेंगी।

'शक्ति कानून' पर नया अपडेट

महिला सुरक्षा के लिए बहुप्रतीक्षित शक्ति कानून पर सुनेत्रा पवार ने स्थिति साफ की। 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू हुई 'भारतीय न्याय संहिता' के कारण पुराने विधेयक को वापस ले लिया गया है। अब डीजीपी कमेटी की सिफारिशों के साथ एक नया और अपडेटेड प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कानून का रूप दिया जाएगा।

'आदिशक्ती अभियान' और चौथी महिला नीति

राज्य सरकार ने 'चौथी महिला नीति' को जमीन पर उतार दिया है। ग्रामीण इलाकों के लिए 'आदिशक्ती अभियान' शुरू किया गया है, जिसका मकसद गांवों को बाल विवाह और अत्याचार से मुक्त करना है। सरकार का खास ध्यान इस बात पर है कि लड़कियां स्कूल न छोड़ें (ड्रॉप-आउट दर कम हो) और पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनें।

पेज-3 भी देखें

ब्रीफ न्यूज़

रिश्वत का मतलब अपराध की आय अर्जित करना : हाईकोर्ट

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल ईडी द्वारा धनशोधन मामले में गिरफ्तार वसई विरार नगर निगम के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि रिश्वत लेने का मतलब अपराध की आय अर्जित करना है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने सोमवार को वीवीसीएमसी के नगर नियोजन विभाग के पूर्व उप निदेशक वाई शिव रेड्डी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और एक विशेष अदालत द्वारा पारित बाद के रिमांड आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। रेड्डी पिछले साल अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ मूल अपराध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके आवासों पर तलाशी लेने के बाद दर्ज किया गया था।

93,000 से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति अटकी

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद में स्वीकार किया है कि राज्य के 'महाडीबीटी' पोर्टल पर उच्च शिक्षा के लिए 93,326 छात्रवृत्ति आवेदन वर्तमान में सत्यापन के लिए लंबित हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने एमएलसी मनीषा कायंदे के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि आवश्यक दस्तावेजों की कमी, कॉलेजों में आवेदन की प्रति जमा न करने या पोर्टल पर गलत जानकारी अपलोड करने के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित हुई है। हालांकि, विभागीय जांच में तेजी लाने के निर्देश के बाद लंबित आवेदनों की संख्या 1.42 लाख से घटकर अब 93 हजार के करीब रह गई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से 2026 के बीच 14 विभिन्न योजनाओं के तहत 7.80 लाख से अधिक छात्रों को 708.41 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है।

बजट चर्चा से गायब अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

▸▸अधिकारियों की गैर-मौजूदगी पर बरसे विधानसभा अध्यक्ष

धीरज सिंह । मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य के वरिष्ठ नौकरशाहों को सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी जारी की। नार्वेकर ने बजट जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भारी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के दौरान प्रशासनिक ढिलाई को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

'इसे अंतिम चेतावनी समझें'

सदन को संबोधित करते हुए राहुल नार्वेकर ने कड़े शब्दों में कहा, ₹वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए यह मेरी तरफ से अंतिम चेतावनी है; इसे आखिरी मौका समझें।₹ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब सदन में बजट जैसे नीतिगत विषयों पर बहस होती है, तो संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पहले भी लिखित रूप में निर्देश दिए थे, लेकिन उनका पालन न होना सदन की गरिमा का अपमान है।

मंत्रियों को डेटा मिलने में हो रही देरी, दंडात्मक कार्रवाई के संकेत

नार्वेकर ने रेखांकित किया कि चर्चा के दौरान मंत्रियों को तत्काल सांख्यिकीय जानकारी और प्रशासनिक इनपुट की आवश्यकता होती है, जो अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण बाधित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ACS स्तर के अधिकारी महत्वपूर्ण सत्रों से नदारद पाए जाते हैं, तो सदन उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा।

वर्ली में बनेगा न्यूयॉर्क से भी बेहतर 'सेंट्रल पार्क'

कैबिनेट मंत्री उदय सामंत का आश्वासन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में विश्वास दिलाया है कि मुंबई के वर्ली (रेसकोर्स की जमीन) पर प्रस्तावित 'सेंट्रल पार्क' परियोजना का किसी भी कीमत पर व्यवसायीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने सदन में दावा किया कि यह पार्क अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से भी बेहतर और अत्याधुनिक होगा। शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक सचिन अहीर, अनिल परब और कांग्रेस के सतेज पाटिल द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए सामंत ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना को लेकर फैली आशंकाएं निराधार हैं और मुंबईवासियों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। परियोजना के तहत समुद्र किनारे बनने वाले हेलीपैड को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने सफाई दी कि इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस हेलीपैड की सुविधाएं केवल विशिष्ट वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सामान्य नागरिक भी इसका उपयोग कर सकेंगे।

पारदर्शिता के लिए विधायकों को दिया जाएगा प्रेजेंटेशन

विपक्ष द्वारा हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देने और रेमंड समूह को हेलीपैड का काम सौंपने के आरोपों के बीच, सरकार ने पारदर्शिता बरतने का निर्णय लिया है। उदय सामंत ने निर्देश दिया है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त भूषण गगराणी मुंबई के सभी विधायकों के सामने इस पूरी परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। 102 वास्तुकारों द्वारा विरोध में लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि उस पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए विरोध के बजाय सभी को इस विकास कार्य में सहयोग करना चाहिए।

विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे को अपशब्द कहना पड़ा भारी

एनसीपी कार्यकर्ता सूर्यकांत मोरे को 30 दिन जेल की सजा

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति में संवैधानिक पदों की गरिमा को लेकर एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला लिया गया है। विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के कार्यकर्ता सूर्यकांत मोरे को अध्यक्ष राम शिंदे के खिलाफ ₹अपमानजनक और अभद्र₹ भाषा का प्रयोग करने का दोषी पाया है। समिति ने मंगलवार को मोरे के लिए 30 दिनों के दीवानी कारावास की सिफारिश की है। यह मामला नवंबर 2024 का है, जब कर्जत-जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र में एक विवाद के दौरान मोरे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन अध्यक्ष राम शिंदे के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' मामला

विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष और भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड ने सदन में रिपोर्ट पेश करते हुए इस घटना को 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' (विरल से विरलतम) श्रेणी में रखा। लाड ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है, बल्कि उच्च सदन की प्रतिष्ठा और संवैधानिक ढांचे पर हमला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवैधानिक अधिकारियों को निशाना बनाने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए यह सजा आवश्यक है। समिति का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से भविष्य में सार्वजनिक जीवन में भाषाई मर्यादा बनी रहेगी।

तकनीकी पेंच और सजा की निरंतरता का प्रस्ताव

सजा के क्रियान्वयन को लेकर एक तकनीकी पेंच भी सामने आया है, क्योंकि विधान परिषद का मौजूदा सत्र 25 मार्च को समाप्त हो रहा है और नियमों के मुताबिक सत्र खत्म होते ही दीवानी सजा भी समाप्त हो जाती है। इस बाधा को दूर करने के लिए प्रसाद लाड ने एक विशिष्ट सिफारिश की है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि यदि वर्तमान सत्र के दौरान मोरे की 30 दिनों की जेल अवधि पूरी नहीं होती है, तो शेष दिनों का कारावास विधान परिषद के अगले सत्र के दौरान पूरा कराया जाए।

डीआरडीओ-नौसेना का कारनामा अब समुद्र के बीच तेजी से पहुंचेगी मदद

स्वदेशी कंटेनर ADC-150 का सफल परीक्षण

एजेंसी । नई दिल्ली

भारत की समुद्री सुरक्षा और नौसेना की ताकत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। डीआरडीओ (DRDO) और भारतीय नौसेना ने मिलकर स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 'एडीसी-150' का गोवा के तट पर सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक गहरे समुद्र में तैनात हमारे जहाजों के लिए 'संजीवनी' साबित होगी।

कठिन परिस्थितियों में 'अग्निपरीक्षा' पास

21 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच गोवा के तट पर पी8आई (P8I) विमान के जरिए कुल चार परीक्षण किए गए। ये सभी ट्रायल अलग-अलग और बहुत चुनौतीपूर्ण समुद्री स्थितियों में किए गए, जिनमें यह स्वदेशी कंटेनर पूरी तरह खरा उतरा। यह भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है।

150 किलो की 'आपातकालीन' रसद

यह कंटेनर 150 किलो तक का भार उठाने में सक्षम है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र के बीचों-बीच तैनात उन जहाजों तक तुरंत रसद (Logistics) पहुँचाना है, जो तट से सैकड़ों मील दूर हैं। आपात स्थिति में जब किसी जहाज को जरूरी स्पेयर पार्ट्स, उपकरण या दवाइयों की तत्काल जरूरत होगी, तब इसे आसमान से सीधे पैराशूट के जरिए गिराया जा सकेगा।

नौसेना की बढ़ती पहुँच और क्षमता

अभी तक समुद्र के बीच रसद पहुँचाने के लिए जहाजों को वापस तट पर आना पड़ता था या हेलीकॉप्टर का इंतजार करना पड़ता था, जिसकी एक सीमा होती है। 'एडीसी-150' के आने से भारतीय नौसेना की रसद पहुँचाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और गहरे समुद्र में हमारे नौसैनिकों को संकट के समय तेजी से सहायता मिल सकेगी।

चार शहरों की मेहनत का 'संगम'

इस तकनीक को तैयार करने में भारत के चार प्रमुख संस्थानों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है:

- विशाखापत्तनम (NSTL): इस पूरे प्रोजेक्ट की मुख्य लैब।
- आगरा (ADRDE): इसका विशेष पैराशूट सिस्टम तैयार किया।
- बेंगलुरु (CEMILAC): उड़ान के लिए जरूरी सुरक्षा सर्टिफिकेट दिए।
- हैदराबाद (DRDL): परीक्षण के दौरान तकनीकी और उपकरणों की मदद दी।

न्यूज ब्रीफ

दिव्यांगजनों की सहायता राशि में 15 गुना वृद्धि

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राज्य के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। पिछले 30 वर्षों से टूलकिट खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि, जो अब तक मात्र 1,000 रुपये थी, उसे अब 15 गुना बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। अक्सर देखा गया है कि दिव्यांग युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी केवल उपकरणों के अभाव में अपना स्वयं का कार्य शुरू नहीं कर पाते थे। अब 15,000 रुपये की इस बढ़ी हुई राशि से वे अपनी पसंद और हुनर के अनुसार सिलाई मशीन, कंप्यूटर एक्सेसरीज, ब्यूटी पार्लर किट या अन्य आवश्यक तकनीकी उपकरण खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह निवेश दिव्यांगों को 'आश्रित' से 'आत्मनिर्भर' बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का रास्ता चुना है। इसके लिए आवेदक के पास वैध UDID कार्ड और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। राज्य में लगभग 29 लाख 63 हजार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार जिला वार्षिक योजना से विशेष फंड और नौकरियों में 4 प्रतिशत पदोन्नति आरक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है।

डेंटिस्ट छात्रा ने की आत्महत्या, प्रेमी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप

मुंबई। एंटॉप हिल इलाके में 24 वर्षीय दंत चिकित्सा (डेंटिस्ट्री) की स्नातकोत्तर छात्रा स्तुति सोनावणे ने अपने घर में फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उसके 31 वर्षीय प्रेमी फजल मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार सुबह हुई इस हृदयविदारक घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्रा के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस को मौके से छह पन्नों का एक विस्तृत 'सुसाइड नोट' मिला, जिसमें मृतका ने आरोपी द्वारा लगातार किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना का स्पष्ट जिक्र किया है। पुलिस जांच के अनुसार, स्तुति और वर्ली निवासी आरोपी एक साल पहले एक 'डेटिंग ऐप' के जरिए मिले थे और प्रेम संबंध में थे; फिलहाल पुलिस ने मृतका के माता-पिता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी बीमा एजेंट को हिरासत में ले लिया है।

50 लाख की बीमा धोखाधड़ी का पर्दाफाश, डॉक्टर और 4 पुलिसकर्मियों सहित 9 गिरफ्तार

जलगांव। जिले में पुलिस ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बीमा धोखाधड़ी की साजिश का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक व्यक्ति की बीमारी से हुई मौत को सड़क दुर्घटना बताकर 50 लाख रुपये हड़पने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी और चार पुलिसकर्मियों सहित कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि राजेंद्र जाधव नामक व्यक्ति की मृत्यु वास्तव में 2024 में यकृत (लीवर) की बीमारी से हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी, भाई, बीमा एजेंटों और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर कागजों में हेराफेरी की और यह दावा किया कि उसकी मौत 2025 में एक सड़क दुर्घटना में हुई है।

ग्राउंड पर 'पावर' के लिए इंजेक्शन का सहारा

पुलिस भर्ती में डोपिंग का मामला
नवी मुंबई पुलिस भर्ती में 4 उम्मीदवार गिरफ्तार, पास से मिले उत्तेजक इंजेक्शन

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

कलंबोली स्थित पुलिस मुख्यालय में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शारीरिक परीक्षण में खुद को बेहतर साबित करने के लिए 'शॉर्टकट' अपना रहे चार उम्मीदवारों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। इन युवकों के पास से उत्तेजक इंजेक्शन और सुइयां बरामद की गई हैं। सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे कलंबोली (रोडपाली) स्थित पुलिस मुख्यालय में जब शारीरिक परीक्षण की तैयारी चल रही थी, तभी पुलिसकर्मियों को चार उम्मीदवारों पर शक हुआ। तलाशी लेने पर उनके पास से शरीर की क्षमता बढ़ाने वाले प्रतिबंधित इंजेक्शन और सुइयां बरामद हुईं। पकड़े गए युवकों की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच है।

अहिल्यानगर और पुणे के युवक शामिल

पकड़े गए चार आरोपियों में से तीन अहिल्यानगर (पूर्व नाम अहमदनगर) जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक युवक पुणे जिले का निवासी है। पुलिस बनने का सपना लेकर आए इन युवकों ने नियमों की धज्जियां उड़ाईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर कलंबोली पुलिस थाने ले जाया गया।

पुलिस सहआयुक्त की 'दो टूक' सलाह

नवी मुंबई के पुलिस सहआयुक्त संजय येनपुरे ने इस घटना पर दुख और चिंता जताई है। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे ऐसे जानलेवा शॉर्टकट से बचें। उन्होंने चेतावनी दी कि ये इंजेक्शन न केवल करियर बर्बाद करते हैं, बल्कि दिल और दिमाग पर भी घातक असर डालते हैं। जो उम्मीदवार शुरुआत में ही बेईमानी का रास्ता चुनते हैं, वे पुलिस सेवा में कभी सफल नहीं हो सकते।

527 पदों के लिए 54 हजार दावेदार

नवी मुंबई पुलिस में सिपाही, चालक और बैंड्समैन के कुल 527 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए करीब 54 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। रोजाना 1500 से 2000 उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए पुलिस ने प्रक्रिया सुबह जल्दी शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने इस सुविधा का गलत फायदा उठाने की कोशिश की।

सख्त धाराओं में मामला दर्ज

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कोते के निर्देश पर चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223, 62 और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इन युवकों का पुलिस बनने का सपना कानूनी कार्रवाई के जाल में फंस गया है।

उल्हासनगर-4 के मुख्य बाजार की सूरत बदलेगी

वीनस से ओटी चौक तक सड़क होगी चौड़ी

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

उल्हासनगर-4 के मुख्य बाजार में वर्षों से जारी ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने कमर कस ली है। विकास योजना (DP) के अनुसार, वीनस चौक से ओटी चौक तक की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। वर्तमान में अतिक्रमण के कारण यह सड़क मात्र 30 फीट की रह गई है, जिसे बढ़ाकर 60 फीट (18 मीटर) करने का प्रस्ताव है।

अतिक्रमण और प्रदूषण से परेशान नागरिक

स्थानीय नागरिकों की शिकायत है कि सड़क संकरी होने और दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर लोहे के जाल लगाकर किए गए अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बची है। ट्रैफिक जाम की वजह से क्षेत्र में वायु और ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक रूप से बढ़ गया है। इस संबंध में स्थानीय शिवसेना नेता और नगरसेवक चंद्रशेखर यादव ने स्पष्ट किया कि बाजार की जरूरतों को देखते हुए 60 फीट चौड़ी सड़क अनिवार्य है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया के दौरान दुकानदारों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी न हो।

पुनर्वास की मांग और नगर रचना विभाग की आगामी कार्रवाई

चौड़ीकरण की राह में सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित होने वाले व्यापारियों का प्रबंधन है। व्यापारी संघ के जगदीश तेजवानी ने मांग की है कि सड़क चौड़ी करने से पहले उन 150 दुकानदारों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए जिनकी दुकानें इसकी जद में आएंगी। दूसरी ओर, मनपा के कार्यकारी अभियंता नीलेश शिरसाथ ने बताया कि नगर रचनाकार विभाग जल्द ही सड़क की सटीक माप करेगा और अवैध अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

यूपी-बिहार जाने वालों की बल्ले-बल्ले

मध्य रेल चलाएगा 176 स्पेशल ट्रेनें
मुंबई और पुणे से गोरखपुर-दानापुर के लिए रोजाना चलेंगी गाड़ियां

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मध्य रेल ने उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। आगामी त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए, मुंबई और पुणे से गोरखपुर व दानापुर के लिए कुल 176 विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का निर्णय लिया गया है।

पुणे से गोरखपुर और दानापुर

पुणे से ट्रेन संख्या 01415 रोजाना सुबह 6:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 4:00 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। वापसी के लिए 01416 शाम 5:30 बजे गोरखपुर से निकलेगी। यह ट्रेन अहिल्यानगर (अहमदनगर), मनमाड, इटारसी और कानपुर के रास्ते अपनी दूरी तय करेगी। पुणे से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन संख्या 01449 दोपहर 3:30 बजे निकलेगी और तीसरे दिन तड़के दानापुर पहुँचेगी। वापसी में 01450 सुबह 5:00 बजे दानापुर से चलकर पुणे आएगी। इस ट्रेन में भी पर्याप्त स्लीपर और जनरल कोच की व्यवस्था की गई है ताकि आम यात्रियों को जगह मिल सके।

सीएसएमटी से गोरखपुर: रोजाना का सफर

ट्रेन संख्या 01079 प्रतिदिन रात 10:30 बजे मुंबई से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह गोरखपुर पहुँचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01080 दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से चलकर तीसरे दिन रात को मुंबई आएगी। यह ट्रेन नाशिक, भुसावल, भोपाल, झांसी और लखनऊ होते हुए जाएगी। इसमें एसी-2, एसी-3 के साथ 9 स्लीपर और 4 जनरल कोच होंगे।

एलटीटी से दानापुर: बिहार जाने वालों के लिए राहत

मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से ट्रेन संख्या 01143 रोजाना सुबह 10:30 बजे निकलेगी और अगले दिन शाम को दानापुर (पटना के पास) पहुँचेगी। वापसी में 01144 रात 9:30 बजे दानापुर से चलकर मुंबई आएगी। यह ट्रेन जबलपुर, प्रयागराज छिवकी और दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

48 चोरियों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

1.39 करोड़ का सोना बरामद

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

मुंब्रा पुलिस और ठाणे क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी चोरियों से इलाके के लोगों की नींद उड़ा रखी थी। इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने 48 अलग-अलग वारदातों की गुत्थी सुलझा ली है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने करोड़ों का सोना बरामद किया है। काफी समय से मुंब्रा इलाके में दिनदहाड़े हो रही चोरियों ने लोगों को दहशत में डाल दिया था। पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे के मार्गदर्शन में मुंब्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने जाल बिछाया। तकनीक और मुखबिरों की सटीक जानकारी के आधार पर पुलिस ने शिवाजी गोपाल साटे (39 वर्ष) को टिटवाला ईस्ट के गणेशवाड़ी इलाके से धर दबोचा।

48 वारदातों का 'एक ही' विलेन

पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आरोपी ने कबूल किया कि पिछले 3 सालों में उसने केवल मुंब्रा पुलिस स्टेशन की सीमा में ही 48 घरों के ताले तोड़े हैं। वह लोहे की रॉड से खिड़कियों की ग्रिल और दरवाजों के ताले मिनटों में तोड़कर सोना लेकर फरार हो जाता था।

पुलिस की 'स्पेशल टीम' का कमाल

इस पूरे ऑपरेशन में सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। सीनियर इंस्पेक्टर सचिन गायकवाड़ और सब-इंस्पेक्टर दीपक घुगे की टीम ने दिन-रात मेहनत कर आरोपी का पीछा किया। यह कार्रवाई टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक का योगदान रहा। आरोपी के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की विभिन्न धाराओं (331-3, 339-4, 305-A) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

करोड़ों के गहनों की बरामदगी

पुलिस ने आरोपी के पास से 1.03 किलोग्राम सोने के गहने बरामद किए हैं। बाजार में इस सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ 39 लाख रुपये आंकी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद होना मुंब्रा पुलिस की कार्यकुशलता का एक बड़ा प्रमाण है।

मनपा का बजट होने वाला है 'भक्कम'

आयुक्त ने स्थायी समिति को सौंपा 1,439 करोड़ का मूल बजट
16 मार्च को होगी अंतिम सभा

विनय दूबे | भाईंदर

मीरा भाईंदर महानगरपालिका के आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मनपा का राजस्व बजट तैयार कर अंतिम मंजूरी हेतु स्थायी समिति को सौंप दिया है। यह बजट सभी विभागों के प्रमुखों द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराए गए लिखित और मौखिक आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की राष्ट्रीय लेखा नियमावली के अनुसार तैयार इस बजट में कुछ पुराने करों को कम किया गया है।

बजट का गणित: 'अ' और 'क' श्रेणी का आवंटन

आयुक्त द्वारा स्थायी समिति के सभापति हसमुख गहलोत को प्रस्तुत किए गए बजट अनुमानों में स्वयं वित्तपोषित ₹अ₹ बजट 1204.17 करोड़ और ₹क₹ बजट 234.84 करोड़ रखा गया है। इस प्रकार कुल मूल बजट 1439.02 करोड़ का है।

विशेष तथ्य

वर्ष 2023 से 2025 तक प्रशासक द्वारा बजट मंजूर किया गया था, लेकिन अब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की महासभा इसे अंतिम मंजूरी देगी। पिछले वर्ष का बजट 2,694.89 करोड़ था, जबकि इस वर्ष मनपा और राज्य सरकार की निधि मिलाकर कुल बजट लगभग 4,500 करोड़ होने का अनुमान है।

स्वच्छ शहर से 'सतत शहर' की ओर बढ़ता कदम

बजट पेश करते हुए आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने कहा, स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद, हमारा अगला लक्ष्य अब 'स्वच्छ शहर से सतत शहर' की ओर बढ़ना है।

महाराष्ट्र में 5,500 से अधिक प्राध्यापकों की मेगा भर्ती

जून तक प्रक्रिया होगी पूरी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विधान परिषद में घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 5,000 से ज्यादा प्राध्यापकों (Professors) की मेगा भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक मंजूरी दे दी है। सरकार का लक्ष्य है कि शैक्षणिक सत्र को सुचारू बनाने के लिए यह पूरी चयन प्रक्रिया जून 2026 से पहले पूरी कर ली जाए।

11,918 रिक्तियों में से पहले चरण की मंजूरी

सदन में कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री पाटिल ने बताया कि राज्य में प्राध्यापकों के कुल 31,185 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से वर्तमान में 19,267 पद भरे हुए हैं। शेष 11,918 रिक्तियों में से फिलहाल 5,012 नए पदों और 494 पुराने बैलेंस पदों को मिलाकर कुल साढ़े पांच हजार से ज्यादा नियुक्तियों को हरी झंडी मिली है। कॉलेजों द्वारा रोस्टर पूरा करने और एनओसी (NOC) मिलने के तुरंत बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पाटिल ने आश्वासन दिया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता पर आधारित होगी। भर्ती के साथ-साथ सरकार ने अनुभवी शिक्षकों को बनाए रखने के लिए प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। इसके अलावा, कॉलेजों में छात्र संख्या के आधार पर पदों के पुनर्वितरण के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय से छात्र संख्या प्रमाणित होने के बाद पदों का आवंटन फिर से किया जाएगा। मंत्री पाटिल ने स्पष्ट किया कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स कॉलेजों की तरह ही सैलरी और ग्रांट के नियम लागू होंगे, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों का स्थाई समाधान होगा।

रिक्शा से महिला का पर्स छीनने वाले 'बॉडी' को चार साल की जेल

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

एक स्थानीय अदालत ने चार साल पुराने लूट के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी श्रेयस उर्फ 'बॉडी' सुजीत पडवल (20) को दोषी करार दिया है। मामला साल 2020 का है, जब आरोपी ने कोपरी पुलिस स्टेशन की सीमा में चलती रिक्शा में बैठी 39 वर्षीय महिला स्पूर्ति गदमशेट्टी लक्ष्मीनारायण का पर्स जबरन छीन लिया था। ठाणे कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिजीत विजय कुलकर्णी ने गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।

कोर्ट में सरकारी पक्ष रहा मजबूत, 2000 रुपये का जुर्माना भी लगा

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रमिला चव्हाण जाधव ने कोर्ट में ठोस तरीके से सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने अहम दस्तावेज और चश्मदीदों के बयान पेश कर साबित किया कि आरोपी ने किस तरह महिला के साथ छीना-झपटी कर चोरी की कोशिश की थी। दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट कुलकर्णी ने पडवल को चार साल की कड़ी कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस टीम की जांच और मुस्तैदी लाई रंग

इस केस की सफल जांच सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर निशिकांत विश्वकर के मार्गदर्शन में असिस्टेंट पुलिस सब-इंस्पेक्टर टी.एन. डुंबरे ने पूरी की थी। पुलिस ने समय पर चार्जशीट फाइल की और गवाहों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ड्यूटी ऑफिसर पुलिस कांस्टेबल विजय सनप और नितेश कुंभार ने भी अदालती कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मनसे नेता की कार फूँकी

बुर्का पहनकर दिया वारदात को अंजाम

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

उल्हासनगर के बिड़ला मंदिर परिसर में मंगलवार तड़के एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मनसे (MNS) के शहर संघटक मैनुदिन शेख की उनके कार्यालय के बाहर खड़ी 'इनोवा' कार को एक अज्ञात हमलावर ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सुबह करीब 4 बजे एक अज्ञात व्यक्ति अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहनकर आया और बोतल में लाया गया पेट्रोल गाड़ी पर छिड़ककर आग लगा दी।

राजनीतिक साजिश की आशंका; सीसीटीवी में कैद हुई घटना

उल्हासनगर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने जिस तरह बुर्के का सहारा लेकर अपनी पहचान छिपाई, उससे यह पूर्व-नियोजित हमला जान पड़ता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी के आने-जाने के रास्ते को ट्रैक कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही असली मकसद सामने आ पाएगा।

कट-ऑफ डेट के बाद 'टेट' पास करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति वैध

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक मानवीय और राहत भरा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति अभय जे. मंत्री की पीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षक निर्धारित 'कट-ऑफ' तारीख के बाद भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास कर लेते हैं, तो उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी जा सकती है। अदालत ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) के शिक्षा विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 31 मार्च 2019 तक परीक्षा पास न करने का हवाला देकर पांच सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्ति रोकने का निर्णय लिया गया था। अदालत ने फरहीन खान सहित पांच महिला शिक्षिकाओं की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए बीएमसी के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वे 30 दिनों के भीतर इन नियुक्तियों को आधिकारिक मंजूरी प्रदान करें। विभाग ने इससे पहले 27 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी कर इन नियुक्तियों को अवैध ठहराया था। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल तकनीकी तारीख (कट-ऑफ डेट) के आधार पर योग्य शिक्षिकाओं को सेवा से वंचित नहीं रखा जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन याचिकाकर्ताओं को सभी सेवा लाभ उनकी परीक्षा पास करने की तिथि, यानी 7 जुलाई 2019 से ही देय होंगे। हाई कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही भविष्य के लिए भी एक रूपरेखा तय कर दी है।

सुबह जल्दी आने पर शाम को जल्दी जाने की मिलेगी छूट

मुंबई की वर्किंग महिलाओं को '30 मिनट' का तोहफा

सुनेत्रा पवार ने किया 'जल्दी आओ-जल्दी जाओ' नीति का ऐलान

दीपक पवार । मुंबई

महाराष्ट्र विधान परिषद में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक चर्चा हुई, जिसका जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में काम करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया। सरकार ने महिलाओं के कार्य-जीवन संतुलन को सुधारने और 'रश आवर' की भीड़ से बचाने के लिए 'जल्दी आओ-जल्दी जाओ' की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।

क्या है 'जल्दी आओ-जल्दी जाओ' का गणित

मुंबई और आसपास के इलाकों में लोकल ट्रेनों और बसों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने यह लचीला नियम बनाया है। अब महिला कर्मचारी अगर सुबह 9.15 से 9.45 के बीच ऑफिस जल्दी पहुँचती हैं, तो उन्हें शाम को उतने ही मिनट (करीब 30 मिनट) जल्दी घर जाने की इजाजत होगी। इससे उन्हें घर की जिम्मेदारियों और सफर की थकान के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

सुरक्षा के लिए 'ऑपरेशन मुस्कान' और 'भरोसा सेल'

उपमुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि लापता बच्चों को ढूँढने के लिए 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत अब तक 42,594 बच्चे खोजे गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य भर में 51 'भरोसा सेल' सक्रिय हैं। इसके अलावा, CSMT, चर्चगेट और बोरीवली जैसे प्रमुख स्टेशनों पर साइबर अपराध रोकने के लिए आधुनिक सिस्टम भी लगाए गए हैं।

आर्थिक मजबूती: 'लड़की बहिन' से 'लखपति दीदी' तक

राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई स्कीमें चला रही है। 'लड़की बहिन', 'लेक लड़की', और 'अन्नपूर्णा' जैसी योजनाओं के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के उत्पादों को बाजार देने के लिए उम्मेद मॉल और महालक्ष्मी सरस जैसी पहल की जा रही है। अब ये उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिक रहे हैं।

मैटरनिटी लीव और आंगनवाड़ी पर जोर

सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन की मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) को मंजूरी दी है। जरूरत पड़ने पर इसके बाद एक साल तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 'हाफ-पे लीव' भी ली जा सकती है। साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने और केंद्रों में पीने के पानी जैसी सुविधाएं देने पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है।

संजय गांधी नेशनल पार्क के अतिक्रमणकारियों का जल्द होगा पुनर्वास: नाइक

मुंबई। संजय गांधी नेशनल पार्क इलाके में सालों से रह रहे पात्र अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। वन मंत्री गणेश नाइक ने विधान परिषद में सदस्य प्रवीण दरेकर के सुझाव का जवाब देते हुए यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि नेशनल पार्क क्षेत्र में मानव बस्तियों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से योजना पर काम कर रही है। इस मुद्दे को हल करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में एक विशेष बैठक भी बुलाई गई है।

मंत्री नाइक ने सदन को बताया कि पहले चरण में कुल 11,359 अतिक्रमणकारियों के दावों की गहन जांच की गई, जिनमें से 299 परिवार पात्र पाए गए हैं। हालांकि इनका पुनर्वास अभी लंबित है, लेकिन सरकार इसे प्राथमिकता पर ले रही है। दूसरे चरण में 13,486 अन्य अतिक्रमणकारियों के दस्तावेजों और दावों पर विचार किया जा रहा है। पुनर्वास योजना के तहत आरे कॉलोनी की लगभग 20 एकड़ जमीन पर आदिवासी परिवारों को बसाने का प्रस्ताव है। यहाँ लगभग 2,200 परिवारों के लिए आधुनिक 'ग्राउंड प्लस वन' (G+1) घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, मंत्री ने यह भी साफ किया कि जब तक पुनर्वास पूरा नहीं होता, तब तक नेशनल पार्क के बाहर की बस्तियों में पानी की सप्लाई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

मध्य रेल के 12 जांबाज हुए सम्मानित

मुंबई। मध्य रेल के महाप्रबंधक प्रतीक गोस्वामी ने भारतीय रेल की सबसे बड़ी प्राथमिकता यानी 'सुरक्षा' को सुनिश्चित करने वाले 12 जांबाज कर्मचारियों को 'संरक्षा पुरस्कार' से सम्मानित किया है। 10 मार्च को मुंबई के सीएसएमटी में आयोजित इस समारोह में उन रेलकर्मियों की तारीफ की गई, जिनकी तीखी नजर और त्वरित सूझबूझ ने पिछले महीनों में कई बड़े हादसों को टाल दिया। महाप्रबंधक ने प्रत्येक विजेता को पदक, प्रशंसा पत्र और 3500 का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा पूरे रेल परिवार के लिए प्रेरणा है। इस मौके पर प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी चंद्र किशोर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पुणे मंडल: रफ्तार पर लगाम और ट्रैक की सुरक्षा

गैंगमेट विशाल हरपुडे ने गश्त के दौरान पटरी की खराबी (व्हील बर्न) पकड़ी। वहीं, अनिल कुमार ने अपनी ड्यूटी के दौरान 'वंदे भारत एक्सप्रेस' को गति कम करने का संकेत दिया, क्योंकि ट्रेन तय सीमा से ज्यादा तेज दौड़ रही थी। उनकी इस सतर्कता से तकनीकी खराबी या पटरी से उतरने का खतरा टल गया।

मुंबई मंडल: खतरे को भांपने वाले 'सतर्क' प्रहरी

मानखुर्द स्टेशन के मैनेजर जी सी आयसक ने पनवेल लोकल के आखिरी कोच में एल्युमिनियम की पट्टियां फंसी देखीं और तुरंत ट्रेन रुकवाई। वहीं, ट्रेन मैनेजर सुमित कुमार ने कालवा के पास उड़ती धूल देखकर शक होने पर ट्रेन रुकवाई, तो पता चला कि कोच का फ्रेम ही टूटा हुआ था। इन दोनों की मुस्तैदी ने बड़ी दुर्घटना टाल दी। नागपुर मंडल से सबसे ज्यादा 4 वीरों को सम्मानित किया गया। दिगंबर सिंह और विनोद मंगुडे (पुणे) ने 'हॉट एक्सल' (पहियों का ज्यादा गर्म होना) पहचानकर मालगाड़ी को रोका।

भुसावल और सोलापुर: पतंग की डोर से पैसेंजर की जान तक

भुसावल के विनोद कुमार ने बिजली के तारों को पतंग की डोर से 60% तक कटते हुए देखा और तुरंत ठीक कराया, जिससे शॉर्ट सर्किट टला। आरपीएफ के वीरपाल सिंह ने सेवाग्राम एक्सप्रेस से गिरते हुए यात्री की जान बचाई। सोलापुर के अंबदास देवकर ने हुसैन सागर एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट की समस्या को मिनटों में सुलझाकर बिजली सप्लाई बहाल की।

पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामला

सुको ने नाबालिग आरोपी के पिता को दी जमानत

महाराष्ट्र सरकार का विरोध

नई दिल्ली/मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के चर्चित पोर्श कार दुर्घटना मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मंगलवार को उस नाबालिग के पिता को जमानत दे दी, जिस पर 2024 में पुणे में शराब के नशे में पोर्श कार चलाकर दो लोगों की मौत का आरोप है। यह घटना 19 मई, 2024 की है, जब कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के द्वारा शराब के नशे में चलाई जा रही पोर्श कार ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में दो आईटी पेशेवरों को कुचल दिया था।

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने विशाल अग्रवाल को राहत दी है। विशाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए ब्लड सैंपल बदलवाने की साजिश रची थी। वे चाहते थे कि मेडिकल रिपोर्ट में शराब की पुष्टि न हो सके। टॉप कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले के दूसरे सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने यह भी देखा कि आरोपी पिछले 22 महीनों से जेल में बंद है। बेंच ने आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट जो नियम और शर्तें तय करेगा, उनके आधार पर विशाल अग्रवाल को बेल दी जाए।

सरकार ने किया विरोध

महाराष्ट्र सरकार ने इस जमानत का विरोध किया। सरकार का तर्क है कि विशाल अग्रवाल का मामला दूसरे आरोपियों जैसा नहीं है, इसलिए उन्हें बराबरी के आधार पर राहत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विशाल अग्रवाल पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि वे इस मामले के किसी भी गवाह से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वे किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। इससे पहले 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ससून जनरल हॉस्पिटल के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अजय टावरे को भी जमानत दी थी। उन पर ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था।

महाराष्ट्र को मिले पूर्णकालिक राज्यपाल

जिष्णु देव वर्मा ने ली राज्यपाल पद की शपथ

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र को अब अपना नया पूर्णकालिक राज्यपाल मिल गया है। त्रिपुरा के अनुभवी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने मंगलवार को दक्षिण मुंबई स्थित राजभवन (लोकभवन) में आयोजित एक भव्य समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 6 मार्च को की गई इस नियुक्ति के साथ ही राज्य में पिछले कुछ समय से चल रहा अतिरिक्त प्रभार का दौर समाप्त हो गया है।

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हुआ भव्य समारोह

राजभवन में आयोजित इस गरिमामयी समारोह में महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासन के शीर्ष चेहरे मौजूद थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने नए राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इनके अलावा राज्य के मुख्य सचिव, मुंबई की महापौर रितु तावड़े, राज्य पुलिस प्रमुख सदानंद दाते और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने।

पश्चिम रेलवे
विद्युत शक्ति कार्य
वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (शक्ति), मुंबई सेंट्रल, मुंबई,ई-**निविदा क्रमांक : EL-81-36-410-WA-85 दिनांक : 05.03.2026 आमंत्रित करते हैं। कार्य एवं स्थान** : मुंबई मंडल के विरार-सूरत खंड के वलसाड स्टेशन पर 25 मीटर की 1 पिट लाइन तथा 1 टावर वैगन शेड (30 मी × 9 मी × 15 मी) के प्रावधान के संबंध में वलसाड विद्युत (पावर) कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत :** 18,18,728/- **ईएमडी :** 36,400/- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 02.04.2026 तक, 15:00 बजे **निविदा खोलने की तिथि एवं समय :** 02.04.2026, 15:30 बजे विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देखें। 1202
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मेलघाट के अंधेरे को दूर करेगा 'सोलर माइक्रो ग्रिड'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी

मुंबई। कुपोषण और बिजली की कमी से जूझ रहे मेलघाट के दूर-दराज के गांवों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन दुर्गम क्षेत्रों में हर घर को अलग सोलर सिस्टम देने के बजाय पूरे गांव के लिए 'सोलर माइक्रो ग्रिड' स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि घने वन क्षेत्रों और अभयारण्य की सीमाओं के कारण वहां पारंपरिक बिजली लाइनें ले जाना संभव नहीं था, इसलिए अब गांव में ही बड़ी क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट लगाकर बैटरी स्टोरेज के जरिए हर घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी।

विधानसभा में सदस्या सुलभा खोडके द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली कमियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि 2018 में 'सौभाग्य योजना' के तहत व्यक्तिगत ऑफ-ग्रिड सिस्टम दिए गए थे, लेकिन रखरखाव (AMC) की कमी के कारण वे बंद हो गए और गांवों में फिर से अंधेरा छा गया।

मध्य रेल
सोलापुर मण्डल
विद्युत कार्य
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि), मध्य रेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याति प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेल्वे की ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा क्रं : सोला/क.वि./नि/2025/29R2. कार्य का नाम** : सोलापुर मंडल के अनवायर्ड पिट लाइन-साइडिंग का विद्युतीकरण का कार्य। (पुनर्निविदा) **कार्य की अनुमानित लागत** : ₹ 1,53,83,701.79। **बयाना राशि** : ₹ 2,26,900/-। **कार्य पुरा करने की अवधि** : 12 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधता** : 60 दिन। **वेबसाइट पर निविदा बंद होने की तिथि और समय** : दि. 03.04.2026 को 15.00 बजे। EXP-08
टिकट के लिए RailOne App डाउनलोड करे

मध्य रेल
ई-नीलामी की सूचना
मुंबई मंडल, मध्य रेलवे ने ई-नीलामी लीजिंग मॉडयूल के माध्यम से **www.ireps.gov.in** पर नीचे दी गई संपत्तियों कि लीजिंग के लिए ई-नीलामी का आह्वान किया है। इच्छुक बोलीदातओं को ई-नीलामी लीजिंग मॉडयूल में पंजीकृत होना आवश्यक है और ई-नीलामी से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाओं से अनुरोध है कि नीचे उल्लिखित ई-नीलामी के विवरण जानने के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देखें:

क्र.सं.	श्रेणी	उप-श्रेणी	नीलामी प्रारंभ
1	विज्ञापन	ट्रेनों के अंदर और बाहर मोबाइल एसेट्स	13.03.2026, 27.03.2026
		RDN	25.03.2026
		OOH	14.03.2026, 20.03.2026
2	पे एंड पार्किंग	मिश्रित पार्किंग	13.03.2026, 16.03.2026, 18.03.2026, 20.03.2026, 23.03.2026
3	अन्य NFR	6 स्टेशनों पर महिला सुविधा केंद्र (टॉयलेय/वॉशरूम सहित)	17.03.2026
		6 स्टेशनों पर प्रीमियम स्टोर	18.03.2026
		45 स्थानों पर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष (EMR)	23.03.2026
		वंदे भारत ट्रेन (ट्रेन संख्या 22229) में फूड/स्नैक ट्रे	23.03.2026

इसके अलावा विषय नीलामी के संबंध में, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, लॉट/कैटलॉग की वापसी, नीलामी की तिथि या समय में परिवर्तन, विस्तार, स्पष्टीकरण आदि, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर जाना चाहिए।
असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है 985

मुंबई की सड़कों पर हॉकर्स का हुंकार, मंत्रालय तक मार्च

सीआईटीयू के नेतृत्व में राज्यव्यापी आंदोलन; 'हॉकर्स एक्ट' लागू करने की मांग

मुंबई। महाराष्ट्र में हॉकर्स (फेरीवालों) के अधिकारों को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। सीआईटीयू (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस) की अगुवाई में राज्य के सभी जिलों में फेरीवालों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मुंबई में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां हजारों हॉकर्स मंत्रालय तक मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हॉकर्स यूनियनों का कहना है कि 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014' के सेक्शन 3.3 के तहत जब तक सर्वे पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी फेरीवाले के खिलाफ कार्रवाई करना गैरकानूनी है। अभी तक यह तय ही नहीं हुआ है कि कौन 'अधिकृत' है और कौन 'अनधिकृत, ऐसे में बीएमसी और नगरपालिका की कार्रवाई उन्हें भुखमरी की कगार पर धकेल रही है।यूनियन ने एक बहुत ही तार्किक मुद्दा उठाया है—जिन हॉकर्स को सरकार ने एलओआर सर्टिफिकेट दिया है और पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिजनेस के लिए लोन दिया है!

पश्चिम रेलवे
सामग्री प्रबंधन विभाग
अलग-अलग तरह के मेंटेरियल सप्लाई
ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना क्रमांक : S/12/2026, दिनांक : 06.03.2026

क्र.सं	निविदा संख्या	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	T.O.D.
80	10251043	अर्थिंग केबल पूर्ण सेट, जो RCF ड्राइंग संख्या LW-71245 Alt 'd' के अनुरूप हो।	6777 नग	06 अप्रैल 2026
81	27245038C	बैटरी संचालित रेल चैम्फरिंग मशीन, साथ में 5 वर्षों का एएमसी (वार्षिक रखरखाव अनुबंध)।	172 नग	03 अप्रैल 2026

ईएमडी, खरीद संबंधी प्रतिबंधों तथा निविदा की विस्तृत शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in** तथा **wr.indianrailways.gov.in** पर जाएँ। 1198
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फालो करें: X.com/WesternRly

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
क्र. AE/E/24658/SWM/दि. 09.03.2026

अभिरुचि अभिव्यक्ति (EOI)

विभाग	सहायक अभियंता (SWM) 'E' विभाग
विषय	'E' विभाग में SMPA कार्य हेतु एनजीओ संस्था के माध्यम से मजदूर उपलब्ध कराने के संबंध में अभिरुचि अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।
जांच शुल्क (Scrutiny Fees)	रु. 550/- + 18% जीएसटी = रु. 649/-
EOI प्रारंभ एवं समाप्ति समय	दिनांक 11.03.2026, समय 10:30 बजे से दिनांक 17.03.2026, समय 17:00 बजे तक
EOI जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 18.03.2026, समय 13:00 बजे तक
कार्यालय का पता	कार्यालय – सहायक अभियंता, एसडब्ल्यूएम विभाग, 'E' विभाग अमेनिटी बिल्डिंग, सी.एस. नं. 749, मजगांव डिवीजन, MHADA कॉलोनी, रामभाऊ भोगले मार्ग, घोडापदेव, मुंबई – 400033
संपर्क व्यक्ति	एस.ई. (SWM), 'E' विभाग
a) कार्यालय संपर्क नंबर	9920281535
b) ई-मेल	ae01e.swm@mcgm.gov.in

इच्छुक संस्थाएं अधिक जानकारी के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका की वेबसाइट http://portal.mcgm.gov.in पर जाएं। EOI दस्तावेज डाक / कूरियर द्वारा जारी या स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

हस्ता)-
सहायक अभियंता (SWM)
'E' विभाग

पीआरओ/3233/विज्ञा. /2025-26

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर
शहर अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे कार्यालय
ई- निविदा क्र.२८६ (२०२५-२६)

उल्हासनगर महानगरपालिका शहरामधील खालील नमुद कामे योग्य वर्गातील ठेकेदाराकडून निविदा प्रणाली पध्दतीनुसार महानगरपालिकेच्या अटी व शर्तीस अधिन राहून दिनांक ११/०३/२०२६ रोजी निविदा मागविण्याकरीता प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर निविदा प्रणालीबाबत इतर आवश्यक माहिती **https://mahatenders.gov.in/** या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

ई- निविदा क्र, २८६ (२०२५-२६)

अ. क्र.	निविदा क्रमांक	कामाचे नांव	निविदा रक्कम (जी.एस.टी वगळून)	इसारा रक्कम	कालावधी	वर्गवारी
१	उमपा/साबांवि/ नोटीस /२०२५-२६/२८६	उल्हासनगर-४ मधील मुक्तीबोध स्मशानभुमी लगतची संरक्षण भिंत रस्ता रुंदीकरणात बाधित होत असून भिंत निष्कासित करुन नविन संरक्षण भिंत बनविणे	२११८६४४/-	२२०००/-	०३ महिने	NA

सदर निविदा प्रणालीबाबत इतर आवश्यक माहिती **https://mahatenders.gov.in/** या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

जा.क्र. उमपा/ पिआरओ / ५८३/२०२६
दि. १०/०३/२०२६

सही/-
कार्यकारी अभियंता (साबांवि)
उल्हासनगर महानगरपालिका

संपादकीय

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच भारत में महंगाई का सच

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात की खबरों ने भारत में कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। आम चर्चा यह है कि अगर यह संघर्ष बढ़ा तो पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की चीजों के दाम अचानक बढ़ सकते हैं। लेकिन जब इस डर को आंकड़ों और आर्थिक तथ्यों की कसौटी पर परखा जाता है, तो तस्वीर उतनी डरावनी नहीं दिखती जितनी आम लोगों को लग रही है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इस तरह के युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तनाव बढ़ने के बाद कच्चे तेल के दाम में तेजी जरूर आई। कुछ समय के लिए ब्रेंट क्रूड का भाव लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, हालांकि बाद में इसमें गिरावट भी देखी गई और यह लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया। इसका मतलब यह है कि बाजार में उतार-चढ़ाव तो है, लेकिन कीमतें स्थायी रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं टिकी हैं। भारत के लिए तेल की कीमत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। तेल महंगा होने का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है और परिवहन महंगा होने से खाद्य पदार्थों सहित कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि जैसे ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, भारत में महंगाई का डर भी बढ़ने लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेल आयात के स्रोतों को काफी हद तक विविध बनाया है। पहले भारत की बड़ी निर्भरता खाड़ी देशों पर थी, लेकिन अब रूस, अमेरिका और अन्य देशों से भी तेल खरीदा जा रहा है। रूस से अपेक्षाकृत सस्ता कच्चा तेल मिलने से भारतीय रिफाइनरियों को काफी राहत मिली है। यही कारण है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अचानक बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार भी मौजूद हैं। सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए विशाखापत्तनम, मंगलूरु और पाडूर जैसे स्थानों पर तेल भंडारण की व्यवस्था की है। इन भंडारों में लगभग 50 लाख टन से अधिक कच्चा तेल रखा जा सकता है, जो आपूर्ति में बाधा आने पर कुछ समय तक देश की जरूरतों को पूरा कर सकता है। महंगाई के आंकड़े भी इस डर को पूरी तरह सही साबित नहीं करते। हाल के महीनों में भारत की खुदरा महंगाई दर लगभग 5 प्रतिशत के आसपास रही है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य दायरे के भीतर है। यदि तेल की कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी होती भी है, तो सरकार करों में बदलाव या सब्सिडी जैसे उपायों से कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यदि कच्चे तेल की कीमत 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का आयात बिल जरूर बढ़ सकता है और रुपये पर दबाव भी आ सकता है। लेकिन इसका असर तुरंत रोजमर्रा की सभी चीजों की कीमतों पर नहीं पड़ता। महंगाई में वास्तविक बढ़ोतरी तब होती है जब तेल की कीमतें लंबे समय तक बहुत ऊंचे स्तर पर बनी रहें। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान-अमेरिका तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर जरूर पड़ा है, लेकिन भारत में तत्काल महंगाई विस्फोट की आशंका फिलहाल मजबूत नहीं दिखाई देती। इसलिए लोगों के बीच फैला डर पूरी तरह तथ्यों पर आधारित नहीं है। स्थिति पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।

पैकेजिंग प्रिंटिंग का बढ़ता बाजार और संभावनाएं

मुनीब चौरसिया
युवा पत्रकार

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में पैकेजिंग प्रिंटिंग की संभावनाएं और भी अधिक हैं। देश में खाद्य उद्योग, औषधि उद्योग, कृषि उत्पाद, खुदरा व्यापार और उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों में पैकेजिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे-जैसे इन उद्योगों का विस्तार होगा, वैसे-वैसे पैकेजिंग प्रिंटिंग की मांग भी बढ़ती जाएगी।

वर्तमान समय में पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग तेजी से विकसित होने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। बदलती उपभोक्ता आदतों, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आधुनिक बाजार व्यवस्था ने पैकेजिंग को उत्पाद की सफलता का एक अहम हिस्सा बना दिया है। आज किसी भी वस्तु की बिक्री केवल उसकी गुणवत्ता पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी पैकेजिंग और प्रस्तुति भी ग्राहक को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसी कारण पैकेजिंग प्रिंटिंग का बाजार लगातार विस्तार कर रहा है और इसमें भविष्य की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।

पैकेजिंग का मूल उद्देश्य उत्पाद को सुरक्षित रखना और उसे आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना होता है। जब कोई ग्राहक बाजार में किसी वस्तु को देखता है, तो सबसे पहले उसकी नजर पैकेजिंग पर ही जाती है। यदि पैकेट की डिजाइन, रंग संयोजन और प्रिंटिंग आकर्षक हो, तो ग्राहक उस उत्पाद की ओर सहज रूप से आकर्षित हो जाता है। इसलिए कंपनियां अपने उत्पादों की पैकेजिंग को बेहतर बनाने के लिए प्रिंटिंग तकनीकों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। खाद्य पदार्थ, दवाइयां, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और दैनिक उपयोग की चीजों में पैकेजिंग प्रिंटिंग का व्यापक उपयोग हो रहा है।

ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव ने भी पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग को नई दिशा दी है। आज ऑनलाइन खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ा है और लाखों उत्पाद प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। ऐसे में उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत और भरोसेमंद पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही कंपनियां अपने ब्रांड की पहचान बनाए रखने के लिए पैकेजिंग पर विशेष प्रकार की प्रिंटिंग और डिजाइन का उपयोग करती हैं। इससे पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग की मांग और भी बढ़ गई है।

तकनीकी प्रगति ने भी इस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले जहां साधारण छपाई तकनीकों का उपयोग किया जाता था, वहीं आज आधुनिक मशीनों और

डिजिटल तकनीकों ने प्रिंटिंग को अधिक तेज, सटीक और आकर्षक बना दिया है। उन्नत प्रिंटिंग तकनीकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली छपाई, स्पष्ट चित्र और आकर्षक रंग संयोजन संभव हो पाए हैं। इससे कंपनियां अपने उत्पादों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पा रही हैं और बाजार में अपनी पहचान मजबूत बना रही हैं।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में पैकेजिंग प्रिंटिंग की संभावनाएं और भी अधिक हैं। देश में खाद्य उद्योग, औषधि उद्योग, कृषि उत्पाद, खुदरा व्यापार और उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों में पैकेजिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे-जैसे इन उद्योगों का विस्तार होगा, वैसे-वैसे पैकेजिंग प्रिंटिंग की मांग भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी इस क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, जिसका प्रभाव पैकेजिंग उद्योग पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब कंपनियां पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री को अपनाने पर जोर दे रही हैं। पुनर्चक्रण योग्य कागज, जैविक सामग्री और कम प्रदूषण वाली स्याही का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग एक टिकाऊ और जिम्मेदार दिशा की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में हरित प्रिंटिंग तकनीक इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन सकती है।

पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग में रोजगार की भी व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। डिजाइनर, प्रिंटिंग विशेषज्ञ, मशीन ऑपरेटर, गुणवत्ता निरीक्षक और विपणन से जुड़े अनेक पेशेवर इस उद्योग में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे-जैसे बाजार का विस्तार होगा, वैसे-वैसे रोजगार के अवसर भी बढ़ते जाएंगे। इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। हालांकि इस क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। कागज और अन्य कच्चे माल की बढ़ती कीमत, आधुनिक मशीनों में निवेश की आवश्यकता और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा प्रिंटिंग उद्योग के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए और उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए, तो पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है।

समग्र रूप से देखा जाए तो पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग आज विकास के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। बढ़ती उपभोक्ता मांग, ई-कॉमर्स का विस्तार, ब्रांडिंग की आवश्यकता और तकनीकी प्रगति इस क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में यह उद्योग न केवल व्यापार और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पैकेजिंग प्रिंटिंग का बढ़ता बाजार केवल एक व्यावसायिक अवसर ही नहीं, बल्कि आधुनिक उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यदि उद्योग आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर आगे बढ़े, तो भविष्य में यह क्षेत्र और भी अधिक व्यापक और प्रभावशाली रूप में उभर सकता है।

हमारी गीता

भारतीय समाज व्यवस्था और कुलधर्म का महत्व

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद केवल मोह नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सामाजिक चिंता थी। जब अर्जुन युद्ध के परिणामों पर विचार करता है, तो वह 'कुलक्षय' और 'कुलधर्म' के नष्ट होने का भय व्यक्त करता है। आज की युवा पीढ़ी को शायद ये शब्द पुराने लगें, लेकिन एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में पारिवारिक व्यवस्था ही वह आधारशिला है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

परिवार: समाज की प्राथमिक इकाई

भारतीय संस्कृति में समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि परिवारों का संगठन है। जैसे एक-एक मजबूत ईंट से भव्य भवन खड़ा होता है, वैसे ही संस्कारित परिवारों से एक समर्थ राष्ट्र बनता है। हमारी प्राचीन कुटुंब प्रधान व्यवस्था में व्यक्ति अकेले नहीं गढ़ा जाता था; वह अपने दादा, चाचा और पिता के सान्निध्य में एक वृहद् परिवेश में विकसित होता था। यह व्यवस्था किसी तानाशाही पर नहीं, बल्कि 'विधि-निषेध' यानी अनुशासन और मर्यादाओं पर टिकी थी।

कुलधर्म और आज का संकट

वर्तमान समय में 'Standard of Living' (जीवन स्तर) को ऊँचा उठाने की होड़ तो है, परंतु 'Standard of Life' (जीवन के

मूल्य) कहीं पीछे छूट गए हैं। आज का युवा आत्मसंयमन और अनुशासन के अभाव में केवल क्षणिक सुख को ही जीवन का ध्येय मान बैठा है। बुजुर्गों के मार्गदर्शन और पारिवारिक शासन के बिना समाज में स्वैराचार बढ़ रहा है। व्यसन, अनियंत्रित संबंध और अपनी मर्जी को ही सर्वोपरि मानना इसी कुलक्षय का आधुनिक रूप है।

सामाजिक सुख और एकात्मता

अर्जुन का भय यह था कि जब कुल की स्त्रियां असुरक्षित होंगी और वर्ण-संकर स्थिति उत्पन्न होगी, तो पूरी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है—संस्कारों का लोप। जब परिवार में अनुशासन नहीं होता, तो समाज में अराजकता फैलती है। सामाजिक सुख और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पारिवारिक एकात्मता अनिवार्य है।

शख्सियत

कैप्टन अमरिंदर सिंह

सेना की अनुशासनबद्धता से राजनीति के शिखर तक

भारतीय राजनीति के फलक पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी पहचान केवल उनके पद से नहीं, बल्कि उनके अडिग चरित्र, राजसी गरिमा और सैन्य अनुशासन से होती है। पटियाला रियासत के वारिस और पंजाब के दो बार मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसा ही नाम हैं। उनका जीवन एक सैन्य अधिकारी के साहस और एक राजनेता की दूरदर्शिता का अनूठा संगम है, जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

11 मार्च 1942 को पटियाला के शाही परिवार में जन्मे अमरिंदर सिंह का पालन-पोषण ऐश्वर्य के बीच हुआ, लेकिन उनके संस्कारों में देश सेवा सर्वोपरि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में प्रशिक्षण लिया। 1963 में वे भारतीय सेना में शामिल हुए। हालांकि, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने 1965 के प्रारंभ में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब 1965 का भारत-पाक युद्ध छिड़ा, तो उन्होंने अपनी सुख-सुविधाओं को त्याग कर पुनः सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध के दौरान 'सिख रेजिमेंट' में कप्तान के रूप में अपनी सेवाएँ दीं और युद्ध के मैदान में अदम्य साहस का परिचय दिया। उनका यह निर्णय सिखाता है कि राष्ट्र की पुकार पर व्यक्तिगत हितों का त्याग करना ही सच्ची वीरता है।

सेना छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। कैप्टन की राजनीति कभी भी केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं रही, बल्कि वे हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 1984 के 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के विरोध में उन्होंने संसद की सदस्यता और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। यह उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने सिद्ध किया कि उनके लिए सामुदायिक भावना और नैतिकता, पद से कहीं ऊपर है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो कार्यकालों (2002-2007 और 2017-2021) के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनके नेतृत्व में पंजाब ने कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। विशेष रूप से 2004 में 'पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट' पारित कर उन्होंने पंजाब के जल हितों की रक्षा की, जिसके लिए उन्हें 'पंजाब का पानी बचाने वाला नायक' कहा गया। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता उनकी 'पहुंच' थी; वे एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने शाही पृष्ठभूमि के बावजूद आम जनता और किसानों की समस्याओं को गहराई से समझा।

2017 में जब उन्होंने दोबारा सत्ता संभाली, तो पंजाब नशीली दवाओं के संकट और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा था। कैप्टन ने 'नशा मुक्त पंजाब' के संकल्प के साथ कड़े प्रशासनिक कदम उठाए। उनके नेतृत्व की असली परीक्षा कोविड-19 महामारी के दौरान हुई। पंजाब देश के उन पहले राज्यों में था जिसने सख्त कर्फ्यू और प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन के जरिए संक्रमण की गति को रोकने का प्रयास किया। एक सैन्य अधिकारी की तरह उन्होंने संकट के समय 'कमांड' संभाली और जनता के बीच सुरक्षा का भाव पैदा किया।

जीवन ऊर्जा

डगलस एडम्स ब्रिटेन के प्रसिद्ध लेखक, व्यंग्यकार और रेडियो नाटककार थे। उनका जन्म 11 मार्च 1952 को कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में हुआ। वे विज्ञान कथा को अनोखे हास्य और कल्पनाशील शैली में प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्ध कृति द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी ने उन्हें विश्वभर में लोकप्रिय बनाया। उनका निधन 11 मई 2001 को अमेरिका में हुआ।

डगलस एडम्स : जन्म - 11 मार्च 1952

जन्म

सोचने की आदत ही मनुष्य को अलग बनाती है

जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम प्रश्न पूछना बंद न करें। कल्पना वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कभी घबराइए मत। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम अभी उसे समझने की शुरुआत ही कर रहे हैं। हास्य जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देता है। तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मनुष्य की मदद करे। जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला कदम है। हर उत्तर एक नया प्रश्न पैदा करता है। दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी हम समझते हैं। सोचने की आदत ही मनुष्य को अलग बनाती है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है सही सवाल पूछना। कभी-कभी सबसे अजीब विचार

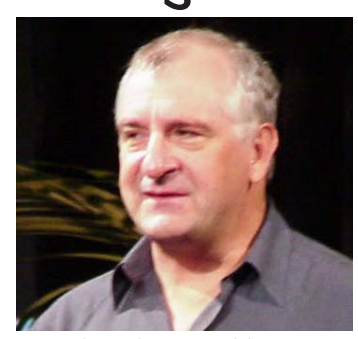

ही सबसे अच्छे साबित होते हैं। समय एक अजीब और रहस्यमय चीज है। हंसी सबसे अच्छी समझदारी है। जीवन में आश्चर्य बनाए रखना जरूरी है। ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। नई चीजें सीखना जीवन को रोचक बनाता है। दुनिया को समझने के लिए कल्पना जरूरी है। हास्य हमें वास्तविकता से भागने नहीं बल्कि उसे समझने में मदद करता है।

असंभव केवल तब तक असंभव है जब तक हम उसे समझ नहीं लेते। विचारों की स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत है। हर समस्या में एक कहानी छिपी होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जिज्ञासा है। कभी-कभी उत्तर बहुत सरल होते हैं। जीवन एक अद्भुत यात्रा है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है। रचनात्मकता सीमाओं को तोड़ती है। हास्य और बुद्धि साथ-साथ चलते हैं। भविष्य कल्पना से जन्म लेता है। प्रश्न पूछना ज्ञान की शुरुआत है।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन

भारतीय दर्शन और लोक कथाओं में 'अन्न' को केवल उदर पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य की सूक्ष्म चेतना और संस्कारों का निर्माता माना गया है। एक अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा के माध्यम से ऋषि-मुनियों ने यह समझाया है कि हमारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य किस प्रकार प्रकृति के चक्र में घूमकर अंततः हमारे ही अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। इस जिज्ञासा की शुरुआत एक ऋषि के मन में उठे उस प्रश्न से होती है, जिसमें उन्होंने सोचा कि यदि प्रतिवर्ष करोड़ों लोग अपने पाप धोने गंगा में जाते हैं, तो निश्चित ही गंगा भी उन पापों के बोझ से पापी हो गई होगी। अपनी इस शंका के समाधान हेतु उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। जब ऋषि ने अपना प्रश्न देवताओं के सम्मुख रखा, तो स्वयं भगवान ने उन्हें सत्य के साक्षात्कार हेतु प्रकृति के विभिन्न

तत्वों के पास ले जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि कर्म और उसके फल के गहन विज्ञान को समझने की एक आध्यात्मिक यात्रा थी। त्य की खोज में जब ऋषि और देवता माँ गंगा के तट पर पहुँचे और उनसे उनके पापी होने का प्रश्न किया, तो गंगा ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि वे पापी नहीं हैं, क्योंकि वे उन समस्त पापों को अपने भीतर रोकती नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाहित होकर उन्हें सागर को अर्पित कर देती हैं। जिज्ञासु दल जब विशाल समुद्र के पास पहुँचा, तो सागर ने भी स्वयं को निष्पाप बताते हुए कहा कि वह उन समस्त अशुद्धियों और पापों को सूर्य की तपन से भाप बनाकर बादलों के रूप में आकाश की ओर भेज देता है। अंततः जब वे बादलों के पास पहुँचे, तो बादलों ने स्पष्ट किया कि वे भी उन पापों को अपने पास नहीं रखते, बल्कि वर्षा की बूंदों के रूप में उन्हें पुनः धरती पर बरसा देते हैं। प्रकृति का यह चक्र दर्शाता है कि कोई भी ऊर्जा—चाहे वह पाप की हो या पुण्य की—कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि वह अपना रूप बदलकर पुनः उसी स्रोत की ओर लौटती है जहाँ से उसका उद्भव हुआ था। वर्षा की यही बूंदें जब पृथ्वी की उर्वर शक्ति से मिलती हैं, तो 'अन्न' का सृजन होता है। यही वह बिंदु है जहाँ प्रकृति का भौतिक चक्र मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक चक्र से जुड़ जाता है। बादलों ने ऋषि को समझाया कि वही पापयुक्त या अशुद्ध ऊर्जा अन्न के माध्यम से पुनः मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। शास्त्रों का यह अटल सिद्धांत है कि 'अन्न' जिस मानसिक स्थिति, वृत्ति और कमाई से प्राप्त किया जाता है, उसी के अनुरूप मनुष्य की मानसिकता और स्वभाव का निर्माण होता है। यदि अन्न बेईमानी, छल या किसी के शोषण से अर्जित धन से खरीदा गया है, तो वह भोजन शरीर में जाकर तामसी प्रवृत्तियाँ, क्रोध और अशांति पैदा करता है। अन्न का प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि वह न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे विचारों की दिशा और हमारे चरित्र की शुद्धता को भी निर्धारित करता है, क्योंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है।

अतः जीवन की सार्थकता और मानसिक शांति के लिए अनिवार्य है कि हम अपने भोजन की शुचिता पर विशेष ध्यान दें। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह पूर्णतः ईमानदारी और कठोर परिश्रम का होना चाहिए, क्योंकि अन्याय की कमाई से आया एक भी दाना बुद्धि को भ्रमित करने की क्षमता रखता है। साथ ही, भोजन पकाते समय और उसे ग्रहण करते समय मन की अवस्था अत्यंत शांत, प्रसन्न और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरी होनी चाहिए। जब हम परमात्मा का स्मरण करते हुए सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं, तो वह भोजन अमृत बन जाता है और हमारे भीतर दैवीय गुणों का संचार करता है।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

अपने विचार

कांग्रेस अवैध प्रवासियों को हटाने में दिलचस्पी नहीं रखती क्योंकि वे उसका राजनीतिक वोटबैंक हैं। यदि वह वाकई घुसपैठियों को हटाने के लिए कमिटेड है तो इसे अपने आगामी चुनाव घोषणापत्र में शामिल करें. चुनाव आयोग इस समय असम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसईआर) कर रहा है, जिसमें घुसपैठियों की पहचान की जाएगी।

अमित शाह
गृहमंत्री, भारत सरकार

बिरला जी का व्यक्तिगत रूप से सभी के साथ रिश्ता अच्छा है। हमें यह संकल्प लाना पड़ रहा है। इस सदन की मर्यादा को बचाने और सदन में जनता का विश्वास कायम रखने के लिए धर्म का पालन करते हुए हम यह अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। विपक्ष बिरला पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं कर रहा है।

गौरव गोगोई
नेता, कांग्रेस

टीम इंडिया पर शर्म आती है! जब हमने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता था, तब हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के खिलाड़ी शामिल थे। हम उस ट्रॉफी को अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपने भारत और हिंदुस्तान लेकर आए थे। फिर अब भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी को किसी एक खास जगह पर ही क्यों घुमाया जा रहा है?

कीर्ति आजाद
नेता, टीएमसी

पुरानी संसद में एक बार हम लोग 'अफजल गुरू को फांसी देना है' का नारा लगाते हुए बीच में चले गए थे। उस वक्त हमारे नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने हमें बहुत डांटा था और अपनी जगह से प्रोटेस्ट करने को कहा था। ये 2004 का नवंबर था। आज तो सभी लोग प्रधानमंत्री जी के आगे आ जाते हैं।

किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001

indiagroundreport@gmail.com

भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

टीम इंडिया की विश्व कप जीत पर डाक विभाग का विशेष सम्मान

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारतीय डाक विभाग ने एक अनूठा सम्मान प्रकट किया है। इस गौरवशाली अवसर पर महाराष्ट्र सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने 9 मार्च 2026 को मुंबई में एक 'विशेष रद्दीकरण' जारी किया। इस विशेष विमोचन समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मनोज कुमार, डीपीएस (मेल और बीडी), सिमरन कौर, डीपीएस (मुख्यालय) के साथ-साथ GCCI (ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ-बेस्ड इंडस्ट्रीज) के अध्यक्ष डॉ. वल्लभभाई कथीरिया और निदेशक डॉ. अमिताभ एके भटनागर भी शामिल हुए। इनके अलावा अजय जालान, जिग्नेश पंड्या, प्रफुल्ल भाई और रमेश घेटिया जैसे प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया।

संविधान प्रदर्शनी का उद्घाटन और न्यायिक विमर्श

ठाणे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय ओक ने ठाणे के विद्या प्रसारक मंडल लॉ कॉलेज में भारतीय संविधान की मूल प्रति की एक स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने देश के किसी लॉ कॉलेज में अपनी तरह की पहली पहल बताया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों और प्राचार्य की उपस्थिति में उन्होंने जोर दिया कि छात्रों और नागरिकों को इन चित्रों के माध्यम से अपने संवैधानिक इतिहास को गहराई से समझना चाहिए। प्रदर्शनी के उपरांत 'भारत में आपराधिक सुनवाई प्रक्रिया' पर व्याख्यान देते हुए जस्टिस ओक ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है, जहाँ आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में भी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है। उन्होंने जूरी सिस्टम से आधुनिक प्रक्रिया तक के विकास को समझाते हुए छात्रों को प्रेरित किया कि वे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संतुलित प्रकृति और निष्पक्षता को आत्मसात करें।

मुंबई सेंट्रल से रतलाम तक गूँजा महिला सशक्तिकरण का नारा

पश्चिम रेलवे के सभी छह मंडलों में विविध आयोजन, प्रतिभाओं को मिला प्रोत्साहन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के उपलक्ष्य में महिला शक्ति, उनके स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रमों की एक शानदार श्रृंखला का आयोजन किया। 9 और 10 मार्च को मुंबई के चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल में आयोजित इन कार्यक्रमों ने न केवल महिला कर्मचारियों की प्रतिभा को निखारा, बल्कि कार्यस्थल पर उनके योगदान को एक नई पहचान भी दी।

'सहयोगिनी' के जरिए सुरक्षा का संदेश

10 मार्च को मुंबई सेंट्रल के 'रेल निकुंज' में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने 'सहयोगिनी' नामक पुस्तिका का विमोचन किया। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रति जागरूकता का एक सशक्त माध्यम है। इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है।

युवा प्रतिभाओं का सम्मान

पश्चिम रेलवे ने केवल अपनी कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि उन बालिकाओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। इस सम्मान का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास देना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। महिला दिवस का यह उल्लास केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहा। पश्चिम रेलवे के सभी छह मंडलों—मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और रतलाम—में भी ऐसे ही सार्थक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साबरमती और दाहोद कारखानों के साथ-साथ मुंबई के जगजीवन राम अस्पताल में भी महिला कर्मचारियों के समर्पण और शक्ति को नमन किया गया।

कला, संगीत और आत्मरक्षा का संगम

कार्यक्रम में महिला कर्मचारियों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जहाँ एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव का माहौल बनाया, वहीं मार्शल आर्ट्स के प्रदर्शन ने महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, एक सर्व-महिला बैंड (All-Women Band) की धुनों ने पूरे समारोह में जोश और ऊर्जा भर दी।

'स्वस्थ महिला, स्वस्थ विश्व' की गूँज

9 मार्च को चर्चगेट स्थित मुख्यालय में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। 'माई इंस्पिरेशन– माई स्टोरी' सत्र के माध्यम से महिलाओं ने अपने जीवन के संघर्ष और प्रेरणादायक अनुभवों को कविता और भाषणों के जरिए साझा किया। यहाँ लगाई गई पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रदर्शनी ने साबित कर दिया कि रेल चलाने वाली ये महिलाएँ कला के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं हैं।

बलिराजा फ्री बिजली योजना में 7.5 एचपी की लक्ष्मण रेखा

लिमिट के अंदर खपत लाने पर ही मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा में खेती के लिए बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ किया कि 'मुख्यमंत्री बलिराजा फ्री बिजली योजना' का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी बिजली की खपत 7.5 HP (हॉर्सपावर) की निर्धारित सीमा के भीतर रखनी होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'बलिराजा फ्री बिजली योजना' का ढांचा केवल उन किसानों के लिए बनाया गया है जो 7.5 HP तक के पंप का इस्तेमाल करते हैं।

सांगली मामले की जांच रिपोर्ट

विधायक सत्यजीत देशमुख द्वारा उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शिराला तालुका के 52 बिजली कनेक्शनों की मौके पर जाकर जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि उन किसानों की असल खपत 7.5 HP से अधिक थी, इसलिए उनके बिजली बिल सही थे और उन्हें मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं मिल सका। फडणवीस ने एक तकनीकी पहलू भी साझा किया। उन्होंने बताया कि खेती के पंपों का वर्गीकरण (Classification) महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (MERC) तय करता है, न कि महावितरण। सरकार ने खेती के लिए अलग वर्गीकरण का मुद्दा कमीशन के सामने रखा था, लेकिन फिलहाल उसे मंजूरी नहीं मिली है। वर्तमान में जो किसान 7.5 HP से अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग स्पेशल रेट लागू है। यह रेट सामान्य कमर्शियल रेट से तो अलग है, लेकिन मुफ्त बिजली योजना के दायरे में नहीं आता। ऐसे किसानों के लिए बिल का भुगतान करना अनिवार्य है।

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ बड़ी जंग

मीरा भाईंदर में 14-15 साल की किशोरियों के लिए मुफ्त टीकाकरण

डीबीडी संवाददाता | भाईंदर

मीरा भाईंदर नगर निगम ने महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक निर्णायक जंग छेड़ दी है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, मनपा ने किशोरियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान का आगाज़ किया है। भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण सर्वाइकल कैंसर है। मनपा के मुख्य चिकित्सक डॉ. नंदकिशोर लहाने के अनुसार, लगभग सभी मामले ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) के संक्रमण की वजह से होते हैं। वैक्सीनेशन इस कैंसर को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है, जिससे 93% से 100% तक सुरक्षा मिल सकती है।

किसे और कौन सी वैक्सीन दी जाएगी?

इस अभियान के तहत 14-15 वर्ष की किशोरियों को गार्डासिल-4 वैक्सीन की एक डोज दी जाएगी। यह विशेष रूप से एचपीवी टाइप 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करती है, जो सर्वाइकल कैंसर के सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह विशेष अभियान अगले तीन महीने तक चलाया जाएगा।

सुरक्षा और साइड इफेक्ट्स की हकीकत

डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि यह वैक्सीन पिछले 20 सालों से दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है और पूरी तरह सुरक्षित है। इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, सूजन, थोड़ा बुखार या सिरदर्द जैसे सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जो जल्द ही ठीक हो जाते हैं। इसके कोई बड़े दुष्प्रभाव नहीं हैं। महापौर डिंपल मेहता और स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से सोशल मीडिया पर चल रहे गुमराह करने वाले वीडियो और अधूरी जानकारी को नज़रअंदाज़ करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करें और टीकाकरण कराएं ताकि कोई भी कन्या इस सुरक्षा से वंचित न रहे।

कहाँ और कब लगवायें टीका?

अभिभावकों की सुविधा के लिए यह वैक्सीन मीरा भाईंदर के सभी आरोग्य केंद्रों, भारतरत्न इंदिरा गांधी अस्पताल और भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी सरकारी अस्पताल (भाईंदर पश्चिम) में उपलब्ध है। टीका लगवाने का समय सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तय किया गया है।

भुसावल मंडल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन

डीबीडी संवाददाता | भुसावल

मध्य रेलवे के भुसावल मंडल द्वारा 9 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भुसावल स्थित कृष्णचंद्र सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री पुनीत अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों सहित महिला कल्याण समिति की सदस्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।

500 महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में दिखाया अपना कौशल

इस उत्सव के दौरान विभिन्न रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की धूम रही, जिसमें मंडल की लगभग 500 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की रूपरेखा में रंगोली, नृत्य, गीत गायन, समूह नृत्य और फैंसी ड्रेस जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थीं। अपर मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार सुमन और श्री एम. के. मीना ने भी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को मंडल रेल प्रबंधक पुनीत अग्रवाल के कर-कमलों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दिलीप खरात ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस आयोजन की सफलता में SBF (स्टाफ बेनिफिट फंड) के सदस्यों और कल्याण निरीक्षकों का विशेष तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग रहा।

11,452 मेगावाट का सर्वोच्च विद्युत उत्पादन

महानिर्मिती का 'सुपर पावर' प्रदर्शन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महानिर्मिती ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है, जिसे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 9 मार्च 2026 को कंपनी ने 11,452 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब राज्य में बिजली की मांग 30,400 मेगावाट के पार पहुँच गई थी, तब महानिर्मिती के इंजीनियरों और तकनीशियनों ने दिन-रात एक कर इस चुनौती को अवसर में बदल दिया।

'ऑल-आउट' परफॉरमेंस: 28 की 28 यूनिट्स चालू

इस कीर्तिमान की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से कठिन बात यह रही कि महानिर्मिती की सभी 28 तापीय विद्युत इकाइयाँ एक साथ पूरी क्षमता से चल रही थीं। यह किसी भी पावर कंपनी के लिए तकनीकी प्रबंधन और मेंटेनेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ एक भी यूनिट में तकनीकी खराबी नहीं आई।

मांग 30,000 के पार, फिर भी नहीं लगा 'कट'

महाराष्ट्र में गर्मी और औद्योगिक गतिविधियों के कारण बिजली की मांग 30,400 मेगावाट के ऊपर निकल गई थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोड शेडिंग (बिजली कटौती) का डर रहता है, लेकिन महानिर्मिती के इस रिकॉर्ड उत्पादन ने राज्य की जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की।

कोयना और उरण का 'पावरफुल' बैकअप

तापीय ऊर्जा (कोयला) के साथ-साथ महानिर्मिती ने अपनी अन्य शक्तियों का भी बखूबी इस्तेमाल किया। कोयना जल विद्युत परियोजना और उरण गैस विद्युत केंद्र को आवश्यकतानुसार प्रभावी ढंग से संचालित किया गया, जिससे पीक आवर्स (सबसे ज्यादा मांग वाले समय) में ग्रिड को मजबूती मिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सफलता को राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रबंध निदेशक राधाकृष्णन बी. और संचालक अभय हरणे सहित सभी ग्राउंड लेवल के तकनीशियनों की सराहना की। प्रबंध निदेशक राधाकृष्णन बी. ने स्पष्ट किया कि महानिर्मिती का लक्ष्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। स्थापित क्षमता का 100% उपयोग करना कंपनी की प्राथमिकता है, ताकि भविष्य में बढ़ने वाली मांगों को भी इसी तत्परता से पूरा किया जा सके।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। कोर्ट-कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। प्रसन्नता रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी। पूजा-पाठ में मन लगेगा।

वृष वाहन व मशीनरी इत्यादि के प्रयोग में लापरवाही न करें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। चिंता तथा तनाव रहेंगे। व्यापार ठीक चलेगा।

मिथुन कार्यक्षेत्र के लिए नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। बिगड़े काम बन सकते हैं। समाजसेवा करने का मन बनेगा। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। व्यस्तता रहेगी। आराम का समय नहीं मिलेगा। थकान रहेगी।

कर्क व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

सिंह समाजसेवा करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। मान-सम्मान मिलेगा। खोई हुई वस्तु मिलने के योग हैं। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। शत्रु सक्रिय रहेंगे। जोखिम व जमानत के कार्य बिलकुल न करें।

कन्या शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार अच्छा चलेगा। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी। किसी आनंदोत्सव में भाग ले सकते हैं। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी।

तुला किसी तरह से बड़ा लाभ होने की संभावना है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। किसी तरह के विवाद में विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में नया कार्य मिल सकता है।

वृश्चिक कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। थकान व कमजोरी रह सकती है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। दूसरों से अधिक अपेक्षा न करें। बेवजह चिड़चिड़ापन रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। कार्य में मन नहीं लगेगा।

धनु भावना में बहकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। नौकरी में कार्यभार रहेगा। लाभ होगा। स्वास्थ्य के संबंध में लापरवाही न करें। स्वास्थ्य पर व्यय होगा। दुःखद समाचार मिल सकता है। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। कुसंगति से हानि होगी।

मकर मनपसंद व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग अपने कार्य उत्साह व लगन से कर पाएगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। प्रमाद न करें।

कुंभ घर, दुकान, फैक्टरी व शोरूम इत्यादि के खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। कारोबार में बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। रुके काम बनेंगे। घर-बाहर उत्साह व प्रसन्नता से काम कर पाएंगे।

मीन प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में मातहत साथ देंगे।

परंपरा, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन की प्राचीन मान्यता

प्रियंका जैन
97699 94439

भारतीय परंपरा में धातुओं का उपयोग केवल सजावट या विलासिता के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी गुणों को भी महत्व दिया जाता था। प्राचीन काल से ही सोना, चांदी, तांबा और कांसा जैसी धातुओं को जीवनशैली का हिस्सा बनाया गया। इनमें चांदी को विशेष रूप से शुद्ध और उपयोगी धातु माना गया है। आयुर्वेद और पारंपरिक मान्यताओं में यह विश्वास किया जाता रहा है कि चांदी के बर्तन में रखा पानी पीना शरीर के लिए कई प्रकार से लाभकारी हो सकता है। आज भले ही आधुनिक जीवनशैली ने कई पारंपरिक आदतों को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन धीरे-धीरे लोग फिर से इन प्राचीन तरीकों की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं।

भारतीय घरों में पहले अक्सर चांदी के गिलास, कटोरी या लोटे में पानी रखने और पीने की परंपरा होती थी। विशेष अवसरों पर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी इसका उपयोग किया जाता था। बुजुर्गों का मानना था कि चांदी के बर्तन में रखा पानी शरीर को शुद्ध और संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी चांदी को एक ऐसी धातु माना गया है जो शरीर के कई कार्यों को संतुलित रखने में मदद कर सकती है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, चांदी के बर्तन में रखा पानी त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में सहायक माना जाता है। माना जाता है कि यह शरीर के अंदर से संतुलन बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। कई लोग यह भी मानते हैं कि नियमित रूप से ऐसे पानी का सेवन करने से त्वचा अधिक साफ और ताजगी भरी महसूस हो सकती है। एक और मान्यता यह भी है कि चांदी के बर्तन में रखा पानी शरीर की अत्यधिक गर्मी को संतुलित करने में सहायक हो सकता है। आयुर्वेद में शरीर के तापमान और ऊर्जा संतुलन को महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि चांदी की प्रकृति शीतल होती है, इसलिए इससे जुड़ी चीजें शरीर में ठंडक का अनुभव कराने में सहायक मानी जाती हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से यह भी कहा गया है कि चांदी के बर्तन में रखा पानी स्मरण शक्ति को समर्थन देने में सहायक हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि चांदी का संबंध मानसिक शांति और स्थिरता से जोड़ा गया है। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि इसका नियमित उपयोग मानसिक संतुलन और ध्यान क्षमता को बनाए रखने में सहायक हो सकता है।

कुछ लोगों के अनुभवों में यह भी पाया गया है कि चांदी के बर्तन में रखा पानी भूख की समस्या में मददगार हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका पाचन तंत्र कमजोर होता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह पाचन को संतुलित रखने और शरीर के सामान्य कार्यों को सुचारु बनाए रखने में सहायक माना जाता है। परंपरागत रूप से यह भी माना गया है कि चांदी के बर्तन में रखा पानी लीवर के सामान्य कार्यों को समर्थन दे सकता है। आयुर्वेद में लीवर को शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जो शरीर को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि चांदी से संबंधित वस्तुओं का उपयोग शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को संतुलित करने में सहायक हो सकता है। फेफड़ों के स्वास्थ्य के संदर्भ में भी पारंपरिक मान्यताओं में चांदी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि चांदी के बर्तन में रखा पानी फेफड़ों के सामान्य स्वास्थ्य को समर्थन देने में सहायक हो सकता है।

हर गांव के पास होगी रोडवेज बस

- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को कैबिनेट की मंजूरी
- योगी की कैबिनेट ने 30 अन्य प्रस्तावों पर जताई सहमति

एजेंसी । लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026" को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राज्य की सभी ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई गई है।बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और राजस्व मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने संयुक्त रूप से कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की सभी लगभग 59 हजार ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ना है। वर्तमान में करीब 12 हजार ग्राम सभाएं ऐसी हैं, जहां नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं है।

28 सीटों वाली बसों का होगा संचालन

उन्होंने बताया कि ग्रामीण मार्गों पर छोटी बसों का संचालन किया जाएगा, जिनकी क्षमता लगभग 28 सीटों की होगी। इन बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के साथ अनुबंध के आधार पर कराया जाएगा। किराये का निर्धारण प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करेगी। यही समिति बसों के अनुबंध और संचालन से जुड़े अन्य निर्णय भी लेगी।

योजना के तहत बसों का समय निर्धारण ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ताकि लोग आसानी से जिला मुख्यालय तक आ-जा सकें और अपने काम निपटाकर समय पर गांव लौट सकें। कैबिनेट बैठक में परिवहन व्यवस्था से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया।

ओला-उबर को करवाना होगा पंजीकरण

इस नए निर्णय के अनुसार ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं संचालित करने वाली कंपनियों Ola और Uber को अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण हर पांच वर्ष में पांच हजार रुपये शुल्क देकर नवीनीकृत कराना होगा, जिससे राज्य में संचालित ऐसे वाहनों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

ऐप पर मिलेगा चालक का विवरण

परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन निगम एक विशेष मोबाइल एप विकसित करेगा, जिसमें इन कंपनियों के वाहनों और चालकों का पूरा विवरण दर्ज रहेगा। इसी तरह संबंधित कंपनियों को भी अपना एप आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि निगम की सभी बसों में पहले से ही जीपीएस प्रणाली लगी हुई है और उनकी नियमित निगरानी की जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब किसी संपत्ति के पंजीकरण से पहले विक्रेता की पहचान और स्वामित्व की पुष्टि खतौनी के आधार पर की जाएगी।

एटा के सीडीओ नागेंद्र मिश्र निलंबित

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एटा के मुख्य विकास अधिकारी नागेंद्र नारायण मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर की गई है। जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सीडीओ पर कथित रूप से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए।नियम-07 के तहत विभागीय जांच शुरू उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नागेंद्र नारायण मिश्र को उनके पद से निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ नियम-07 के तहत विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी अधिकारी के प्रति कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

वरिष्ठ महिला को बनाएंगे परिवार का मुखिया

एजेंसी । भराड़ीसैंण

उत्तराखंड सरकार ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़ों को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को विधानसभा में देवभूमि परिवार विधेयक पेश किया। इस विधेयक के लागू होने पर राज्य में "देवभूमि परिवार" नाम से एक समेकित और प्रमाणित परिवार-आधारित डाटाबेस तैयार किया जाएगा।प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में अलग-अलग मौजूद लाभार्थी सूचनाओं को एक मंच पर लाया जाएगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं का लाभ सही पात्र परिवारों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।

सुशासन की दिशा में मजबूत कदम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक-2026 राज्य में सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ अधिक व्यवस्थित तरीके से पहुंचेगा।

केंद्रीकृत डेटा से आएगी विश्वसनीयता

वर्तमान में अलग-अलग विभाग अपनी योजनाओं के लिए स्वतंत्र लाभार्थी डाटाबेस संचालित करते हैं, जिससे आंकड़ों के दोहराव, बार-बार सत्यापन और विभागीय तालमेल की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। प्रस्तावित प्रणाली के तहत एक केंद्रीकृत डेटा संरचना विकसित की जाएगी, जो विभिन्न विभागों के लिए लाभार्थी जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक-2026 राज्य में सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ अधिक व्यवस्थित तरीके से पहुंचेगा।

2.58 लाख शिक्षकों की दिया नियुक्तिपत्र: नीतीश कुमार

- सुपौल को मिली 569 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात
- समृद्धि यात्रा में सुपौल पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

एजेंसी । सुपौल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के दौरान सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ पूर्ण हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण किया।

हर क्षेत्र का संतुलित विकास आवश्यक

इस दौरान हुई सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य बिहार के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब तक लगभग 2.58 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है।

84 परियोजनाओं का हुआ भूमिपूजन

आधिकारिक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने लगभग 434 करोड़ रुपये की लागत वाली 84 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि करीब 135 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 129 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्मली रिंग बांध का निरीक्षण किया और स्थानीय नागरिकों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया।

सुपौल में आठ नई परियोजनाएं स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने बताया कि सुपौल जिले में आठ नई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है, जिन पर कार्य प्रगति पर है और इनके पूरा होने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

छह साल बाद फिर दौड़ेगी नकहा-लखनऊ पैसेंजर

- कोरोना काल में बंद किया गया था संचालन

एजेंसी । बाराबंकी

पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए नकहा-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को पुनः संचालित करने की तैयारी कर रहा है। यदि विभागीय औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो लगभग छह वर्ष से बंद पड़ी यह ट्रेन जल्द ही फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आ सकती है। यह ट्रेन कोविड-19 महामारी के दौरान 23 मार्च 2020 को बंद कर दी गई थी।

रेल मंत्री से की गई थी मांग

ट्रेन के पुनः संचालन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इसे जल्द शुरू करने का अनुरोध किया था। उन्होंने क्षेत्रीय यात्रियों की सुविधा का हवाला देते हुए नकहा-लखनऊ पैसेंजर सेवा बहाल करने की आवश्यकता बताई थी।मंत्री की पहल के बाद रेलवे प्रशासन ने इस दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। प्रस्तावित योजना के अनुसार इस ट्रेन के मार्ग में आंशिक बदलाव किया जाएगा और अब यह लखनऊ के डालीगंज स्टेशन तक संचालित की जाएगी।

गैंगस्टर शैलेश सिंह की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क

एजेंसी । मीरजापुर

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने एक राइस मिल संचालक की करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ददरा गांव निवासी शैलेश कुमार सिंह की करीब 10 बीघा कृषि भूमि को मंगलवार को कुर्क कर सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर की गई। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही।

कुर्की से पहले करवाई गई मुनादी

प्रशासन ने लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराकर ददरा ग्राम पंचायत की दो बीघा और राजगढ़ ग्रामसभा की आठ बीघा भूमि को कुर्क घोषित किया। इसके बाद जमीन पर कुर्की का बोर्ड लगाकर उसे सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया गया।राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई।

कानपुर में गंगा प्रदूषण रोकने को बड़ा कदम, 14 नालों का टैपिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत

138.11 करोड़ रुपये से साफ होगी गंगा

एजेंसी । कानपुर

औद्योगिक नगरी कानपुर में गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। शहर के 14 प्रमुख नालों को टैप कर उनके गंदे पानी को सीधे गंगा में जाने से रोकने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर करीब 138 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। स्थानीय सांसद रमेश अवस्थी ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना गंगा की स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे नमामि गंगे अभियान को मजबूती देगी।

कानपुर में गंगा प्रदूषण का बड़ा कारण

योजना के तहत जिन नालों से गंदा पानी गंगा में गिरता है, उन्हें इंटरसेप्ट कर उनका प्रवाह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की ओर मोड़ा जाएगा। इससे बिना उपचारित अपशिष्ट जल के नदी में जाने पर रोक लगेगी और गंगा के प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।

कानपुर को जलमार्ग से जोड़ने की मंशा

सांसद अवस्थी ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 को वाराणसी से कानपुर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। फिलहाल यह जलमार्ग वाराणसी से कोलकाता तक संचालित है। यदि इसे लगभग 200 किलोमीटर आगे कानपुर तक विस्तारित किया जाता है, तो क्षेत्र के उद्योगों को जल परिवहन के रूप में सस्ता और सुगम विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

व्यापार जगत

लौटा बाजार, निवेशकों को मिले 6.5 लाख करोड़

- सेंसेक्स में 640 तो निफ्टी में 234 अंकों की तेजी

एजेंसी । मुंबई

लगातार दो कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूत वापसी देखने को मिली। प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में लगभग एक प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 640 अंकों की तेजी के साथ 78,205.98 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 करीब 234 अंक चढ़कर 24,261.60 के स्तर पर पहुंच गया।बाजार में यह सकारात्मक रुख मुख्य रूप से वैश्विक संकेतों और निवेशकों की खरीदारी के कारण देखने को मिला। खासकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के जल्द कम होने की संभावना से निवेशकों का भरोसा बढ़ा।

अमेरिकी डालर में आई कमजोरी

वैश्विक संकेतों की बात करें तो अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट से भी बाजार की धारणा सकारात्मक हुई। विश्लेषकों के अनुसार भू-राजनीतिक जोखिम कम होने के संकेतों के बीच निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में सुधार हुआ है, जिसका असर शेयर बाजार की तेजी के रूप में दिखाई दिया। विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में तेजी के पीछे कई प्रमुख कारण रहे। इनमें पश्चिम एशिया में संघर्ष कम होने की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपये की मजबूती शामिल हैं।

447 लाख करोड़ रुपये हुई पूंजी

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई मिडकैप इंडेक्स करीब 1.66 प्रतिशत और बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स लगभग 2.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए।

बाजार में तेजी के कारण सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर करीब 447 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिससे निवेशकों की संपत्ति में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में तेजी के पीछे कई प्रमुख कारण रहे। इनमें पश्चिम एशिया में संघर्ष कम होने की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपये की मजबूती शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट से ऊर्जा आयात पर दबाव कम होने की संभावना बनी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत मिला। इसके अलावा विदेशी मुद्रा बाजार में भी भारतीय मुद्रा में सुधार देखा गया। कारोबार के अंत में रुपया लगभग 53 पैसे मजबूत होकर 91.80 प्रति डॉलर के आसपास बंद हुआ। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और घरेलू बाजार में खरीदारी को समर्थन मिला। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि हालिया गिरावट के बाद कई मजबूत कंपनियों के शेयर आकर्षक स्तर पर आ गए थे, जिसके चलते निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं और फार्मा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जमकर खरीदारी की।

निर्यातकों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार: गोयल

- मौजूदा हालातों के मद्देजनर उद्योग मंत्री ने कहा- नई संभावनाओं पर हो रहा विचार

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय निर्यातकों को हरसंभव सहायता देने का भरोसा जताया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार निर्यातकों के लिए बीमा सहयोग सहित नई सहायक योजनाओं की संभावनाओं पर विचार कर रही है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित आहार अंतरराष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला के 40वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकार निर्यात क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि निर्यातकों की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा सहायता से जुड़ी नई योजनाओं पर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन सहित संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर केंद्र सरकार का एक अंतर-मंत्रालयी समूह लगातार निगरानी कर रहा है।

अरामको: 18 करोड़ बैरल तेल की आपूर्ति प्रभावित

- पश्चिम एशिया के सैन्य तनाव से ऊर्जा संकट गहराने के आसार

एजेंसी । नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता गहराने लगी है। तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ने के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र में संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। सऊदी अरामको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीन एच. नासिर ने चेतावनी दी है कि ईरान और इज़राइल के साथ-साथ अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से वैश्विक तेल बाजार पर गंभीर असर पड़ सकता है। उनके अनुसार अब तक लगभग 18 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तंत्र पर दबाव बढ़ा है।

होर्मुज तेल सप्लाई का प्रमुख मार्ग

स्थिति को और संवेदनशील बनाने वाला कारक होर्मुज जलडमरूमध्य है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। अनुमान है कि वैश्विक कच्चे तेल की लगभग 17 प्रतिशत आपूर्ति इसी रास्ते से होकर गुजरती है और इसका बड़ा हिस्सा एशियाई देशों को भेजा जाता है। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो इस मार्ग से तेल आपूर्ति रोकने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। ल आपूर्ति में संभावित बाधा को देखते हुए सऊदी अरब वैकल्पिक मार्गों के उपयोग पर जोर दे रहा है। नासिर के अनुसार कंपनी के पास होर्मुज मार्ग को आंशिक रूप से बाईपास करने के लिए ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का विकल्प मौजूद है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल तेल परिवहन किया जा सकता है। यह पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों को लाल सागर के तट से जोड़ती है।

ट्रंप के बयान पर फिलहाल राहत

अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान से जुड़ा सैन्य संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कुछ नरमी देखी गई। फिलहाल ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोनों में गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है।

राहतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता हुआ क्रूड आयल

एजेंसी । नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को राहत मिलने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर कीमतों में यह नरमी उस समय आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ चल रहा सैन्य टकराव जल्द समाप्त हो सकता है। बाजार में आई इस प्रतिक्रिया के कारण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोनों की कीमतों में छह प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई।

सोमवार को आया था भारी उछाल

बताते चलें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था और यह 119 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। हालांकि बाद में संभावित शांति के संकेतों के कारण बाजार की धारणा बदली और कीमतों में गिरावट का रुख।

जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों को राहत

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में प्रस्ताव मंजूर

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश को आंशिक राहत देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इस संबंध में संशोधन को मंजूरी दी गई।

चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार

व्यापार के मोर्चे पर देखा जाए तो चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत का चीन को निर्यात घटकर लगभग 14.25 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात बढ़कर 113.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

कैबिनेट में प्रक्रियात्मक संशोधन पास

बाद में 23 मार्च 2022 को जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे देशों की कोई भी कंपनी या निवेशक भारत में निवेश केवल सरकारी स्वीकृति मार्ग के जरिए ही कर सकेगा। साथ ही, यदि किसी निवेश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी स्वामित्व (बेनिफिशियल ओनरशिप) इन देशों के नागरिकों या संस्थाओं के पास जाता है, तो उसके लिए भी पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी। नई कैबिनेट बैठक में निवेश नियमों में कुछ प्रक्रियात्मक राहत देने के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से जुड़े संशोधन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे दिवाला समाधान प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

चीन से आने वाले निवेश को मिलेगी मदद

सरकारी सूत्रों के अनुसार नए निर्णय से विशेष रूप से चीन से आने वाले निवेश के लिए रास्ता कुछ हद तक आसान हो जाएगा। इससे भारतीय कंपनियों और चीनी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। कई कंपनियां लंबे समय से निवेश नियमों में ढील का इंतजार कर रही थीं।दरअसल, वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने प्रेस नोट 3 जारी कर सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले निवेश पर कड़े प्रावधान लागू किए थे।

मैदान पर 'गर्मी' दिखाना अर्शदीप को पड़ा महंगा

आईसीसी ने लगाया मैच फीस का 15% जुर्माना

एजेंसी । दुबई

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को फाइनल मैच में डेरिल मिचेल पर गेंद फेंकने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सजा दी है। उन पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि, भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया था। इस मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम किया।

आईसीसी ने दी सजा

अर्शदीप सिंह की इस हरकत के लिए खेल की वैश्विक संस्था ने उन पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। उन्हें आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 के उल्लंघन के लिए यह सजा मिली है। अर्शदीप को आईसीसी के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.9 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी पर या उसके पास गलत और/या खतरनाक तरीके से बॉल (या क्रिकेट का कोई और सामान) फेंकने से जुड़ा है। जुर्माने के अलावा अर्शदीप के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया।

जोश में होश खो बैठे अर्शदीप

अर्शदीप और मिचेल के बीच विवाद उस वक्त हुआ जब भारतीय तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड की पारी का 11वीं ओवर डालने आए। ओवर की पांचवीं गेंद पर मिचेल डिफेंसिव शॉट खेला और गेंद बाउंस करते हुए अर्शदीप के पास पहुंची। अर्शदीप ने फॉलो थ्रू में गेंद मिचेल के जांघ पर मार दी। इससे मैदान में थोड़ी देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। अर्शदीप सिंह ने ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डाली, जिसे डेरिल मिचेल ने सीधे पिच की तरफ खेल दिया। इसके बाद अर्शदीप ने विकेट की ओर थ्रो मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिचेल की जांघ पर जा लगी। इससे मिचेल काफी नाराज हो गए और वह आक्रामक अंदाज में अर्शदीप की ओर बढ़ते हुए हाथों से इशारे करते नजर आए। स्थिति थोड़ी गरम होती दिखी, तभी सूर्यकुमार यादव बीच में आए और मिचेल के कंधे पर हाथ रखकर उनसे बात करते हुए माहौल को शांत करने की कोशिश की। उधर अंपायर ने भी अर्शदीप सिंह से बात की। दरअसल, वह थ्रो बिल्कुल जरूरी नहीं था, इसलिए इस पर मैदान पर थोड़ी बहस देखने को मिली थी।

जुर्माने के साथ 'डिमेरिट अंक' की मार

केवल 15% मैच फीस ही नहीं, बल्कि अर्शदीप के अनुशासन रिकॉर्ड (Disciplinary Record) में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया गया है। पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला अपराध है। अगर अगले 24 महीनों में उनके खाते में और अंक जुड़ते हैं, तो उन पर मैच का प्रतिबंध (Ban) भी लग सकता है। भारत ने यह फाइनल मुकाबला 96 रनों के विशाल अंतर से जीता, लेकिन अर्शदीप के लिए व्यक्तिगत रूप से यह मैच मिला-जुला रहा। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 32 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुआ। बुमराह के 4 विकेटों ने भारत की जीत पक्की कर दी थी।

अर्शदीप को हुआ था गलती का अहसास

इस विवाद को लेकर अर्शदीप ने भी मैच के बाद चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी। अर्शदीप ने कहा था, मैं तुरंत भागकर मिचेल से माफी मांगने गया था। जब मैंने गेंद फेंकी तो वह रिवर्स स्विंग हो गई और थ्रो में उन्हें लग गई।

गुजरात टाइटंस में शामिल हुए मैथ्यू हेडन

एजेंसी । अहमदाबाद

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन के लिए गुजरात टाइटंस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को अपना नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को इस बड़े फैसले की आधिकारिक मुनादी कर दी। अपनी नियुक्ति पर देसी तेवर दिखाते हुए हेडन ने साफ कर दिया कि उनका मकसद सिर्फ रन बनवाना नहीं, बल्कि मैदान पर दबदबा बनाना है। उन्होंने कहा, ₹अच्छी बल्लेबाजी तो बस दबाव बनाती है, लेकिन 'शानदार' बल्लेबाजी खेल को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। गुजरात टाइटंस में हम यही कड़क मानक सेट करना चाहते हैं।

सोलंकी को 'गुरु' पर भरोसा: बोले- हेडन का अनुभव होगा जीत का मंत्र

गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने इस फैसले को टीम के सफर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। सोलंकी का मानना है कि हेडन जैसा दिग्गज जब डगआउट में होगा, तो युवाओं का जोश और तकनीक दोनों सातवें आसमान पर होंगे। उन्होंने कहा कि शीर्ष स्तर पर खेलने का हेडन का लंबा अनुभव और उभरती हुई प्रतिभाओं को तराशने का उनका हुनर, आगामी सत्र में टीम के लिए 'तुरुप का इक्का' साबित होगा। टीम मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि हेडन की देखरेख में गुजरात के बल्लेबाज विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देंगे।

बने बल्लेबाजी कोच

पावरप्ले के 'बेताज बादशाह' से गुर सीखेंगे युवा

मैथ्यू हेडन क्रिकेट की दुनिया का वो नाम हैं, जिन्होंने सीमित ओवरों के खेल में 'पावरप्ले' के दौरान आक्रामक बल्लेबाजी की नई परिभाषा लिखी थी। दो बार के वनडे विश्व कप विजेता हेडन का अंतरराष्ट्रीय करियर जितना चमकदार रहा है, आईपीएल में भी उनका रसूख उतना ही तगड़ा रहा है।

न्यूज़ ब्रीफ

युद्ध की छाया में फीफा विश्व कप

डलास। फीफा विश्व कप 2026 के मुख्य संचालन अधिकारी (COO) हेइमो शिर्गी ने स्पष्ट किया है कि आगामी फुटबॉल महाकुंभ को स्थगित करना संभव नहीं है। डलास में अंतरराष्ट्रीय प्रसारण केंद्र में पत्रकारों से बात करते हुए शिर्गी ने कहा कि यह टूर्नामेंट वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा है और इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वर्तमान में अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध के कारण जो वैश्विक उथल-पुथल मची है, उस पर फीफा कड़ी नजर रख रहा है। शिर्गी ने स्वीकार किया कि स्थितियां हर दिन बदल रही हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि सभी अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर जल्द ही कोई ठोस समाधान निकाल लिया जाएगा।

टी-20 विश्व कप विजेता टीम के लिए 131 करोड़ का इनाम

मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी-20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के भव्य पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार राशि पिछली बार (2024) दी गई 125 करोड़ की राशि से 6 करोड़ रुपये अधिक है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि बोर्ड खिलाड़ियों और चयनकर्ताओं की निरंतर सफलता की कामना करता है। यह विशाल धनराशि 15 खिलाड़ियों सहित कोचिंग और सहयोगी स्टाफ के बीच वितरित की जाएगी। पुरस्कार राशि के वितरण की योजना के अनुसार, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम के प्रत्येक 15 खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

राष्ट्रगान नहीं गाने पर विवाद

सिडनी। एएफसी एशियन कप 2026 के उद्घाटन मैच के दौरान ईरान की महिला फुटबॉल टीम द्वारा राष्ट्रगान न गाने का मामला अब अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। इस विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की पांच महिला खिलाड़ियों को मानवीय आधार पर वीजा देकर अपने देश में रहने की अनुमति दे दी है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस फैसले के बाद इन खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर उठ रही चिंताओं को कुछ हद तक राहत मिली है।

ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मंत्री टोनी बर्क ने जानकारी दी कि जिन खिलाड़ियों को मानवीय वीजा दिया गया है, उनमें जहरा घनबारी, जहरा सरबली, फतेमेह पसंदिदेह, अतेफे रमजानजादेह और मोना हमौदी शामिल हैं। सरकार के अनुसार इन खिलाड़ियों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। मानवीय वीजा मिलने के बाद वे ऑस्ट्रेलिया में रह सकती हैं और वहां पढ़ाई या नौकरी करने की भी अनुमति होगी।

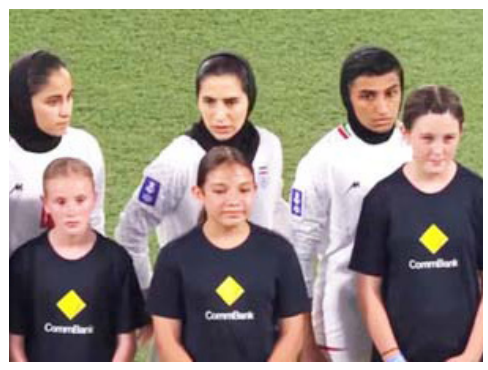

ऑस्ट्रेलिया ने पांच ईरानी महिला फुटबॉलरों को दी शरण

बाकी खिलाड़ियों के लिए भी खुले दरवाजे

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि ईरान की बाकी महिला खिलाड़ी भी वहां रहना चाहें तो उनके लिए भी विकल्प खुले हैं। इस बीच अमेरिका ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका भी इन खिलाड़ियों को शरण देने के लिए तैयार है।

धोनी, रोहित के क्लब में शामिल होना अलग एहसास : सूर्यकुमार

मुंबई। भारत को टी-20 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि वह देश को आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अहमदाबाद से लौटने के बाद मंगलवार को सूर्यकुमार ने अपने घर पर कहा कि 2024 और अब 2026 में ट्रॉफी जीतना बहुत ही खास एहसास है। रोहित और धौनी जैसे दिग्गजों से तुलना किए जाने पर उन्होंने कहा, उस इलीट क्लब में शामिल होकर अच्छा लग रहा है। मैं धीरे-धीरे इसे महसूस कर रहा हूं।

बॉलीवुड

डिफिकल्ट एक्टर हैं पंकज कपूर

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उन कारणों का खुलासा किया है, जिनकी वजह से इंडस्ट्री में उन्हें एक 'डिफिकल्ट एक्टर' (मुश्किल अभिनेता) माना जाता है। पंकज कपूर के अनुसार, यह धारणा उनके करियर के शुरुआती दिनों से जुड़ी है जब वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से मुंबई आए थे। उन्होंने बताया कि उस दौर में अभिनेताओं द्वारा स्क्रिप्ट मांगना आम बात नहीं थी, यहाँ तक कि बड़े सितारे भी बिना स्क्रिप्ट के सेट पर पहुँच जाते थे। जब उन्होंने काम शुरू करने से पहले लिखित पटकथा और चरित्र की बारीकियों की मांग की, तो कई फिल्म निर्माताओं ने उन्हें ₹मुश्किल₹ करार दे दिया। पंकज कपूर का मानना है कि उनकी यह ₹जिद₹ दरअसल उनके काम के प्रति ईमानदारी और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना यह जाने कि उनका किरदार क्या है और कहानी का ढांचा क्या है, वे प्रभावी अभिनय नहीं कर सकते। उन्होंने 'करमचंद' जैसे प्रसिद्ध धारावाहिक के दिनों को याद करते हुए बताया कि शूटिंग से एक दिन पहले स्क्रिप्ट मांगने पर निर्देशक हैरान रह गए थे। हालांकि, उन्होंने बासु चटर्जी, विशाल भारद्वाज और अनुभव सिन्हा जैसे निर्देशकों की सराहना की, जिनके साथ काम करने में उन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका नियोजित और व्यवस्थित था।

वर्कफ्रंट की बात करें तो पंकज कपूर हाल ही में फिल्म 'जब खुली किताब' में नजर आए हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Z5) पर रिलीज हुई है।

रणदीप हुड्डा के घर आई नन्ही परी

रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर फैंस को जानकारी दी है कि वह एक बेटी के पिता बन गए हैं। अपनी नन्ही की पहली झलक अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर साझा की है। वह पिता बनने की खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं। मंगलवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए रणदीप हुड्डा ने फैंस को बताया कि वह एक बेटी के पिता बन गए हैं। एक्टर ने दो तस्वीरें भी साझा की हैं। एक तस्वीर में उनके पिता की गोद में उनकी नवजात बेटी दिख रही है। दूसरी तस्वीर में रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की बेटी के नन्हे हाथ नजर आ रहे हैं। वह अपनी पोस्ट में रणदीप हुड्डा लिखते हैं, 'दादाजी और पोती को जन्मदिन की बहुत बधाई।' 10 मार्च को उनकी बेटी ने जन्म लिया और इसी दिन रणदीप हुड्डा के पिता का जन्मदिन भी होता है। रणदीप हुड्डा अपनी

पोस्ट में पत्नी लिन लैशराम को शुक्रिया कहते हैं। वह लिखते हैं, 'आज जब मैं पिता बना हूं, तो आपका और मेरा रिश्ता गहरा हो गया है, पापा। सबसे जरूरी बात, लिन मुझे पिता बनाने और हमारी छोटी बच्ची को इस दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद। यह बच्ची हमारी जिंदगी है, जिंदगी भर का प्यार है।' रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने साल 2023 में शादी की थी। शादी के दो साल बाद उनके घर किलकारी गूंजी है। वह माता-पिता बने हैं। कपल को पैरेंट्स बनने पर फैंस और करीबी लोगों बधाई दे रहे हैं। रणदीप हुड्डा की इंस्टाग्राम पोस्ट को बॉलीवुड सेलेब्स जैसे दर्शन कुमार और सयानी गुप्ता ने लाइक किया है, रणदीप और लिन को पैरेंट्स बनने पर बधाई दी है।

'जेलर 2' में वर्दी पहने दिखेंगे शाहरुख

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में शाहरुख खान के होने की चर्चा काफी समय से है। इस खबर ने पहले से फैंस को उत्साहित किया था। अब एक ताजा अपडेट इस उत्साह को दोगुना करने आ गया है। खबरों की मानें, तो 'जेलर 2' में शाहरुख की भूमिका को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यह चर्चा तो पहले से थी कि रजनीकांत की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में, शाहरुख का दमदार कैमियो होगा। अब उनकी भूमिका का खुलासा हुआ है।

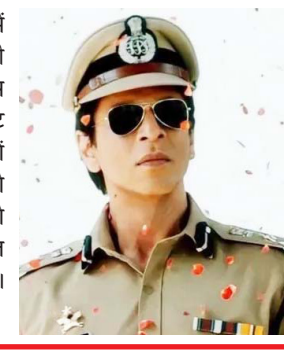

एक्टिंग से ब्रेक ले सकते हैं वरुण धवन

फिल्म 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब एक्टर की अगली फिल्म भी जल्द रिलीज होने वाली है। मगर इससे पहले ही वरुण एक लंबे ब्रेक पर जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह तैयारी भी कर ली है कि वो इन फुरसत के पलों को कैसे बिताएंगे?

इस साल वरुण धवन की कई फिल्में रिलीज हुई हैं। साल के शुरुआत में रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' में एक्टर को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद से ही उन्हें फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। इसी बीच फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वरुण जल्द ही एक्टिंग से लंबा ब्रेक लेने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने काफी कुछ सोच रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक वरुण पहले 'बॉर्डर 2' की शूटिंग और फिर प्रमोशन में काफी व्यस्त थे। अब वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। एक्टर अपनी बेटी लारा के साथ रहना चाहते हैं। इसके चलते ही वो कुछ वक्त के लिए काम से दूरी बना सकते हैं। इस दौरान वह पूरी तरह से अपनी बेटी और परिवार को समय देंगे।

जल्द रिलीज होगी 'है जवानी तो इश्क होना है'

वर्कफ्रंट पर वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है। वरुण के अलावा इसमें मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मौनी रॉय और चंकी पांडे समेत कई कलाकार नजर आएंगे। पहले यह फिल्म 5 जून को रिलीज होने जा रही थी पर अब यह इस साल 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

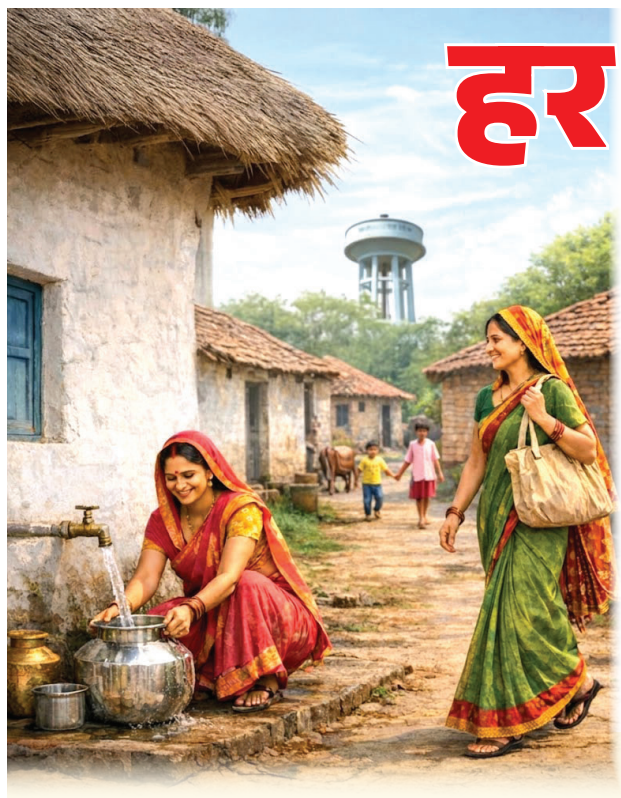

हर घर जल, अब और भी डिजिटल

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में पीने के पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के दूसरे चरण का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई है। इस विस्तार के लिए कुल 8.69 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3.59 लाख करोड़ रुपये होगा।

- जल जीवन मिशन 2.0 को मिली मंजूरी, हर गाँव को मिलेगी अपनी सुजल आईडी
- दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण घर में होगा नल से जल, 8.69 लाख करोड़ का बजट

ढांचागत सुधारों पर रहेगा फोकस

जल जीवन मिशन 2.0 में सरकार ने अब बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बजाय सेवा वितरण पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इसके तहत पूरे देश में एक समान डिजिटल ढांचा सुजलाम भारत लागू किया जाएगा। इसमें हर गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव आईडी दी जाएगी, जिससे स्रोत से लेकर नल तक की पूरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को डिजिटल रूप से मैप किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायतों की बड़ी भूमिका

योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को जल अर्पण प्रक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। कोई भी ग्राम पंचायत खुद को तभी हर घर जल प्रमाणित घोषित कर पाएगी, जब वहां की राज्य सरकारें यह सुनिश्चित कर लेंगी कि गांव स्तर पर संचालन और रखरखाव की पुख्ता व्यवस्था हो गई है। इसके अलावा, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 'जल उत्सव' का आयोजन किया जाएगा।

अब तक की प्रगति और लक्ष्य

आंकड़ों के अनुसार, 2019 में जब यह मिशन शुरू हुआ था, तब देश के केवल 3.23 करोड़ 17 फीसदी ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचता था। वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 15.80 करोड़ (81.61%) परिवारों तक पहुंच गया है। मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। कैबिनेट द्वारा दी गई जानकारी में मिशन के अब तक के सकारात्मक प्रभावों का भी उल्लेख किया गया है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, इस मिशन ने 9 करोड़ महिलाओं को पानी लाने की मेहनत से मुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अनुमान लगाया है कि इस योजना से डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतों को रोकने में मदद मिली है। साथ ही, आईआईएम बैंगलोर और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, इस मिशन ने 59.9 लाख प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने भी अपने आकलन में कहा है कि इसके माध्यम से पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 30% तक की कमी आने की संभावना है।

कैबिनेट की बैठक में अन्य अहम फैसले

मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मान्यता

- बैठक में मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की भी मंजूरी दी गई है। यह निर्णय तमिलनाडु के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बनने से विदेशी यात्रियों का आगमन भी बढ़ेगा।

जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर नया फैसला

- कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक एक नई एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी गई है। यह सड़क क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाएगी और यात्रियों को आसानी से एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद करेगी।

रेल लाइनें: सैंथिया और खड़गपुर के बीच की मंजूरी

- केंद्रीय कैबिनेट ने सैंथिया और पाकुड़ के बीच चौथी रेल लाइन को मंजूरी देने के साथ ही संतारागाछी से खड़गपुर के बीच भी चौथी रेल लाइन का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इससे रेलवे नेटवर्क को विस्तार मिलेगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।

मध्य प्रदेश के हाईवे परियोजना को दी गई हरी झंडी

- इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में हाईवे प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यह प्रोजेक्ट राज्य के विकास के लिए अहम साबित होगा। नए हाईवे के बन जाने से यातायात की गति में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

न्यूज़ ब्रीफ

इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्स का इस्तीफा

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला उस बड़ी ऑपरेशनल गड़बड़ी के करीब तीन महीने बाद आया है, जो पिछले साल दिसंबर में हुई थी। उस समय देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को अपने इतिहास की सबसे बड़ी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। इंडिगो को चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि 10 मार्च 2026 को हुई बोर्ड बैठक में पीटर एल्बर्स का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। कंपनी के बयान के मुताबिक आज से पीटर एल्बर्स कंपनी की सेवाओं से मुक्त हो गए हैं।

एनसीईआरटी ने ज्यूडीशियरी करप्शन चैप्टर पर बिना शर्त माफी मांगी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने किताब के 'ज्यूडीशियरी करप्शन' चैप्टर को लेकर बिना शर्त माफी मांगी है। इस चैप्टर को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। CJI सूर्यकांत ने कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दे सकते। एनसीईआरटी ने प्रेस रिलीज में कहा कि एनसीईआरटी की सोशल साइंस की आठवीं (पार्ट-2) की टेक्स्ट बुक 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी : इंडिया एंड बियॉन्ड' का चैप्टर 4 'द रोल ऑफ ज्यूडीशियरी इन अवर सोसाइटी' था। एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सदस्य इसके लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। पूरी किताब को ही वापस बुला लिया गया है। अब यह उपलब्ध नहीं है।

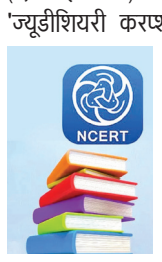

केरल सरकार की अपील पर अभिनेता को नोटिस

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता दिलीप और नौ अन्य लोगों से राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर जवाब मांगा। अपील में 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अपील स्वीकार की, जिसमें राज्य ने दिलीप और तीन अन्य लोगों को मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी है और अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा पाए छह लोगों की सजा को बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। मामले से जुड़े एक सरकारी वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की पीठ ने मामले में दोषी ठहराए गए छह व्यक्तियों और निचली अदालत द्वारा बरी किए गए चार व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।

नौशेरा में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, एक आतंकी ढेर

एजेंसी । राजौरी

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षाबलों ने मंगलवार को घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। खुफिया एजेंसियों से मिले सटीक इनपुट के आधार पर, दोपहर करीब 3 बजे नौशेरा सेक्टर के झांगर इलाके में दो संदिग्ध आतंकवादियों की हलचल देखी गई। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सटीक कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी को मार गिराया। इस मुस्तैदी ने सीमा पार से अशांति फैलाने की एक और नापाक कोशिश को विफल कर दिया है।

घाटी में 'अलर्ट' और सघन तलाशी अभियान जारी

मुठभेड़ के बाद भारतीय सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और दूसरे फरार आतंकवादी की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त कुमुक बुलाई गई है ताकि दुश्मन बचकर न निकल सके। सेना ने स्पष्ट किया है कि वे सीमा पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों में कठुआ और पुंछ क्षेत्रों में भी इसी तरह की ड्रोन घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों की खबरें आई थीं, जिसके बाद पूरी नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है।

तकनीकी और हवाई निगरानी से सीमा की सुरक्षा

घुसपैठ की इस घटना के बाद नौशेरा सेक्टर में जमीनी और हवाई दोनों स्तरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सेना अब आधुनिक उपकरणों और ड्रोन के जरिए दुर्गम इलाकों पर पैनी नजर रख रही है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी साजिश को समय रहते रोका जा सके। पाकिस्तान की नई साजिशों और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की सक्रियता की रिपोर्टों के बीच, भारतीय सेना का यह 'क्विक रिस्पॉन्स' सीमावर्ती निवासियों के लिए राहत लेकर आया है। फिलहाल, झांगर और आसपास के जंगलों में ऑपरेशन अभी भी जारी है।

लोकसभा अध्यक्ष को विपक्ष का माइक बंद करने में महारत: मोइत्रा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के माइक्रोफोन बंद करने की कला में महारत हासिल कर ली है। वे स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रख रही थीं। मोइत्रा ने बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने सदन में बहस के दौरान संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर कई आपत्तियां उठाईं। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सदन में भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को अंत तक बोलने की इजाजत मिलती है, लेकिन जब भी विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तो उनका समय कम कर दिया जाता है। मोइत्रा के अनुसार, स्पीकर ने योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सांसदों की नहीं, बल्कि उन 41 करोड़ भारतीयों की आवाज को दबाने जैसा है जिन्होंने विपक्ष को चुनकर भेजा है।

यूसीसी लागू करने का सही समय: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी । नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता और 1937 के शरीयत कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर मंगलवार को एक बेहद संतुलित और दूरगामी टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि भेदभाव का मुद्दा गंभीर है, लेकिन बिना किसी वैकल्पिक कानून के वर्तमान व्यवस्था को रद्द करना 'कानूनी शून्य' पैदा कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर अदालत 1937 के शरीयत कानून के उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को रद्द कर देती है, तो इसकी जगह कौन सा कानून लेगा? कोर्ट को डर है कि किसी ठोस विकल्प (जैसे UCC) के बिना जल्दबाजी में लिया गया फैसला महिलाओं को वर्तमान से भी कम अधिकार दे सकता है।

भेदभाव का मुद्दा बनाम विधायी अधिकार

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने माना कि याचिका में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का मुद्दा कानूनी रूप से काफी मजबूत है। हालांकि, उन्होंने याद दिलाया कि संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने की जिम्मेदारी 'विधायिका' (संसद) की है, न कि न्यायपालिका की।

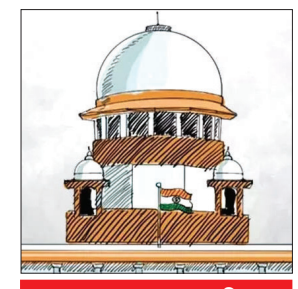

प्रशांत भूषण की 'वैकल्पिक' दलील

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यदि शरीयत कानून की विवादित धाराएं हटाई जाती हैं, तो मुस्लिम परिवारों पर भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि अदालत को यह घोषित करना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। पीठ ने दोहराया कि अदालत पहले भी कई बार संसद से UCC पर विचार करने की सिफारिश कर चुकी है।

कंबाला से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कंबाला के आयोजन को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी ज़िलों के अलावा दूसरे हिस्सों में भैंसों की दौड़ का खेल 'कंबाला' आयोजित करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पूछा कि इसे सिर्फ़ राज्य के एक खास इलाके तक ही क्यों सीमित रखा जाए। कर्नाटक में नवंबर और मार्च के बीच होने वाली कंबाला दौड़ में भैंसों की एक जोड़ी को हल से बांधा जाता है और एक व्यक्ति उसे नियंत्रित करता है। इस प्रतिस्पर्धा में उन्हें एक कीचड़ से भरे ट्रैक में एक साथ दौड़ाया जाता है, जिसमें सबसे तेज़ दौड़ने वाली टीम जीतती है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के 14 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने राज्य को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के दो ज़िलों के बाहर किसी भी जगह को कंबाला के आयोजन के लिए सूचित करने से रोकने की अर्ज़ी को खारिज कर दिया था।

एससी-एसटी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

एजेंसी । नई दिल्ली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण के भीतर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जोयमाल्या बागची शामिल हैं, ने इस याचिका को इसी तरह की राहत मांगने वाली एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया है। पूर्व नौकरशाह ज्ञानेंद्र कुमार खरे द्वारा दायर इस याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

'क्लास के भीतर क्लास' का तर्क : आरक्षण के लाभ का केंद्रीकरण

याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तर्क दिया है कि एससी/एसटी समुदायों के भीतर संपन्न वर्ग यानी 'क्रीमी लेयर' को बाहर न करना असंवैधानिक और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के कारण अवसर केवल एक 'कुलीन वर्ग' के हाथों में सिमट कर रह गए हैं।

प्रियंका-रिजीजू के बीच संसदीय वाकयुद्ध

- रिजीजू ने प्रियंका के बहाने राहुल पर कसा तंज, प्रियंका ने किया पलटवार
- प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया होता तो प्रदर्शन अच्छा होता : रिजीजू
- राहुल अकेले नेता जो 12 साल में सरकार के सामने झुके नहीं : प्रियंका

एजेंसी । नई दिल्ली

लोकसभा में ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने के संकल्प पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल उस समय दिलचस्प हो गया, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच तीखी लेकिन शिष्टाचारपूर्ण जुबानी जंग देखने को मिली। रिजीजू ने प्रियंका की तारीफ के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो प्रियंका ने भी नेहरू और राहुल का जिक्र कर करारा पलटवार किया। इस 'संसदीय वाकयुद्ध' को 'देशज' (Deshi) अंदाज़ में यहाँ इन बिंदुओं में समझा जा सकता है:

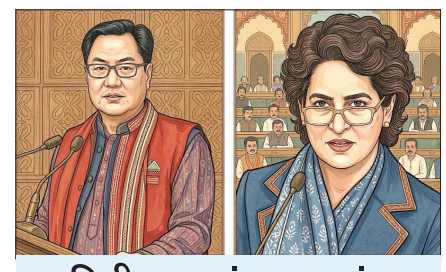

रिजीजू का तंज भरा दांव

चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने राहुल गांधी के सदन में व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष (LoP) बनाया होता, तो विपक्ष का प्रदर्शन शायद ज्यादा बेहतर और गंभीर होता। उन्होंने राहुल की अनुपस्थिति या कम बोलने की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रियंका कम से कम सदन में बैठती और सुनती तो हैं।

लोकतंत्र और नेहरू का जिक्र

प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि सरकार ने कम से कम यह तो माना कि नेहरू जी ने ही लोकतंत्र को मजबूत किया था। उन्होंने कहा कि सच बोलने वाले व्यक्ति (राहुल) को निशाना बनाना आपकी कमजोरी दर्शाता है।

प्रियंका की 'मुस्कुराहट'

जब रिजीजू बोल रहे थे, तब प्रियंका गांधी पीछे बैठकर मुस्कुरा रही थीं। रिजीजू ने इस पर भी चुटकी ली। जब सभापति ने प्रियंका को बोलने का मौका दिया, तो उन्होंने अपनी मुस्कुराहट की वजह साफ की। प्रियंका ने कहा कि उन्हें हंसी इसलिए आई क्योंकि जो भाजपा दिन-रात पंडित नेहरू की आलोचना करती है, आज वही मंत्री अपने पक्ष में नेहरू जी के बयानों का सहारा ले रहे थे और अचानक उनका आदर करने लगे।

भाई की ढाल बनीं प्रियंका

प्रियंका गांधी ने अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बचाव करते हुए उन्हें 'अकेला योद्धा' बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में राहुल गांधी ही वह इकलौते नेता हैं जो सरकार के सामने कभी झुके नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल सदन में बेझिझक सच बोलते हैं, और यही कड़वा सच सत्ता पक्ष को हजम नहीं होता।

रिपोर्ट भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में हर साल आठ प्रतिशत वृद्धि

दुनिया भर के छात्रों की पसंद बन रहा भारत

एजेंसी । नई दिल्ली

भारत अब केवल ज्ञान का निर्यातक ही नहीं, बल्कि दुनिया के छात्रों के लिए एक प्रमुख 'एजुकेशन हब' बनकर उभर रहा है। 'क्यूएस' (QS) की ताज़ा रिपोर्ट 'ग्लोबल स्टूडेंट फ्लोज: इंडिया' के अनुसार, सस्ती पढ़ाई और सुलभ नीतियों की वजह से विदेशी छात्र अब अमेरिका या ब्रिटेन के बजाय भारत का रुख कर रहे हैं। लंदन स्थित संस्था 'क्यूएस' के अनुसार, 2025 में भारत में करीब 58 हजार विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। अनुमान है कि यह संख्या हर साल 8% की दर से बढ़ेगी।

क्यों बदल रहा है छात्रों का मन?

दुनिया भर के छात्र अब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया (बिग-4) जैसे देशों से कतरा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है वहाँ की सख्त वीज़ा नीतियां और पढ़ाई का भारी खर्च। इसके मुकाबले भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा काफी कम खर्च में और आसानी से उपलब्ध है, जो विदेशी छात्रों को आकर्षित कर रही है।

दक्षिण एशिया और अफ्रीका: भारत के 'पावर हाउस'

भारत आने वाले छात्रों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दक्षिण एशिया की है। अकेले नेपाल और बांग्लादेश से 30% से अधिक छात्र आते हैं। वहाँ की बड़ी युवा आबादी के लिए भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है।

'बिग-4' का मोहभंग और भारतीयों की नई मंज़िल

रिपोर्ट के अनुसार, अब भारतीय छात्र भी पारंपरिक देशों (यूएस, यूके आदि) के बजाय जर्मनी, फ्रांस और यूएई जैसे देशों की ओर रुख कर रहे हैं। 2030 तक बिग-4 देशों में भारतीय छात्रों के नामांकन में सालाना 0.5% की गिरावट आ सकती है।

बुनियादी ढांचा: सफलता की असली चाबी

रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है। अगर भारत को अपनी इस शैक्षणिक लोकप्रियता को बनाए रखना है, तो उसे अपने कैंपस, छात्रावास और सहायता सेवाओं में भारी निवेश करना होगा। यदि बुनियादी ढांचा छात्रों की बढ़ती संख्या के बोझ को नहीं संभाल पाया, तो इसका नकारात्मक संदेश जा सकता है।

सीबीएसई गणित के प्रश्न पत्र पर 'रिक रोल'

12वीं गणित पेपर के क्यूआर कोड पर बज रहा गाना

एजेंसी । नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं कक्षा की गणित परीक्षा के दौरान एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 9 मार्च को संपन्न हुई इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पर छपे क्यूआर कोड को जब छात्रों ने स्कैन किया, तो वे हैरान रह गए। कोड को स्कैन करने पर किसी शैक्षणिक सामग्री के बजाय ब्रिटिश गायक रिक एस्टली का 1987 का मशहूर गाना 'नेवर गोना गिव यू अप' का यूट्यूब लिंक खुल रहा है। इंटरनेट की भाषा में इसे 'रिक रोलिंग' कहा जाता है।

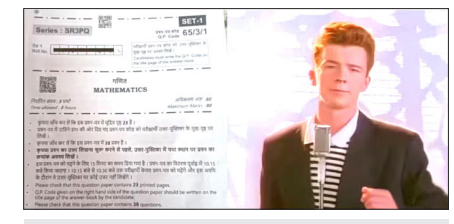

प्रश्न पत्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ, परेशान न हो अभिभावक: बोर्ड

सुरक्षा में सेंध नहीं: सीबीएसई ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सीबीएसई ने स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड का कहना है कि इस घटना से प्रश्न पत्र की सुरक्षा या परीक्षा की शुचिता में कोई सेंध नहीं लगी है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि प्रश्न पत्रों में क्यूआर कोड प्रमाणीकरण और सुरक्षा जांच के लिए दिए जाते हैं। हालांकि एक फिल्मी गाना खुलने से भ्रम की स्थिति पैदा हुई, लेकिन बोर्ड का दावा है कि मुख्य परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित रही है और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है।